मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित
हिन्दी दैनिक

उत्तरशक्ति

हर खबर निष्पक्षता के साथ

मुंबई
वर्षः 8 अंक 171
शनिवार, 03 जनवरी 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

वैवाहिक विवाद में पति का वित्तीय प्रभुत्व क्रूरता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 02 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बिगड़े हुए वैवाहिक संबंध में पति द्वारा अलग रह रही अपनी पत्नी पर वित्तीय प्रभुत्व जमाना क्रूरता का कृत्य नहीं है। शीर्ष अदालत ने साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि किसी आपराधिक मुकदमे को बदला लेने और व्यक्तिगत प्रतिशोध के माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति से अलग रह रही उसकी पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ क्रूरता और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दर्ज कराये गए एक आपराधिक मामले को रद्द करते हुए की।

तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द करते हुए, जिसमें प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया गया था, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, आरोपी-अपीलकर्ता का मौद्रिक और वित्तीय दबदबा, जैसा कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता संख्या दो द्वारा आरोप लगाया गया है, किसी क्रूरता के मामले के रूप में नहीं देखा जा सकता, विशेषकर जब उससे कोई ठोस मानसिक या शारीरिक क्षति उत्पन्न नहीं हुई हो।

उन्होंने कहा, यह स्थिति भारतीय समाज का आईना है, जहां घरों के पुरुष अक्सर महिलाओं के वित्तीय मामलों पर प्रभुत्व जमाने और नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी आपराधिक मुकदमे को बदला लेने या व्यक्तिगत प्रतिशोध के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पीठ की ओर से फैसला लिखने वाली न्यायमूर्ति नागरत्ना ने व्यक्ति द्वारा अलग रह रही अपनी पत्नी को भेजे गए पैसों के खर्च का विवरण मांगे जान को क्रूरता का कृत्य मानने से भी इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, अदालतों को शिकायतों से निपटते समय अत्यंत सतर्क और सावधान रहना चाहिए और वैवाहिक मामलों में व्यवहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, जहां आरोपों की जांच बड़ी सावधानी और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से की जानी चाहिए, ताकि कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके।

उन्नीस दिसंबर का यह फैसला उस अपील पर आया जो पति ने उच्च न्यायालय के 27 अप्रैल 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की थी, जिसमें उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार किया गया था।

इंदौर में हुई मौतों पर भी प्रधानमंत्री हमेशा की तरह मौन हैं : मल्लिकार्जुन खरगे

इंदौर, 02 जनवरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इंदौर में दूषित पानी पीने के कारण कई लोगों की मौत की घटना को लेकर शुक्रवार को दावा किया कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा की तरह इस मामले पर भी मौन हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जल जीवन मिशन समेत, हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली हो रही है।

खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले नरेन्द्र मोदी जी, हमेशा की तरह इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर मौन हैं। यह वही इंदौर शहर है जिसने केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार आठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। ये शर्मनाक बात है कि यहां पर भाजपा के निकम्मेपन के चलते लोग साफ पानी के मोहताज हैं।

उन्होंने दावा किया कि 11 साल से देश केवल लंबे-चौड़े भाषण, झूठ-प्रपंच, खोखले दावे, डबल-इंजन की डींगें सुन रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, जब मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है तो वो गाली-गलौज पर उतर आते हैं। सत्ता के अहंकार में उल्टा पत्रकार पर हावी हो जाते हैं। भाजपा सरकारों के कुशासन पर पूरी मशीनरी पर्दा डालने में जुट जाती है।

खरगे ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन समेत, हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली है। उनका कहना था, याद दिलाना जरूरी है कि इस मिशन के तहत जल जीवन मिशन का 10 प्रतिशत धन दूषित पानी को साफ करने के लिए दिया जाता है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, मोदी सरकार और भाजपा ने ना देश को साफ पानी मुहैया कराया है और ना ही स्वच्छ हवा। आम जनता भुगत रही है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप से 10 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। बहरहाल, स्थानीय नागरिकों ने इस प्रकोप से छह माह के बच्चे समेत 14 लोगों के दम तोड़ने का दावा किया है। इस दावे की स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि नहीं की है।

इंदौर-दिल्ली त्रासदी पर भड़के अभिषेक बनर्जी, बोले- बीजेपी की डबल इंजन सरकार हुई फेल

कोलकता, 02 जनवरी। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इंदौर जल त्रासदी और दिल्ली के विषाक्त प्रदूषण को 'दोहरे इंजन' शासन की विफलता बताते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। पश्चिम बंगाल में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत करते हुए बनर्जी ने मध्य प्रदेश में दूषित पानी से 10 लोगों की मौत और दिल्ली के खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (अदक) के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य आपातकाल का मुद्दा उठाया। अधिकतम तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी रही, हालांकि इसमें मामूली सुधार दर्ज किया गया। सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 302 रिकॉर्ड किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के वर्गीकरण के अनुसार, 0 से 50 के बीच एक्यूआई अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर माना जाता है। सीपीसीबी के समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार, 19 निगरानी केंद्र बहुत खराब, 15 खराब और एक गंभीर श्रेणी में रहा। एनएसआईटी द्वारका में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई, जहां एक्यूआई 423 रहा। बृहस्पतिवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआई 380 था।

वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार, चार जनवरी तक वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी रहने की संभावना है और इसके बाद के छह दिनों में भी इसी तरह की स्थिति रहने के आसार हैं।

अपनी हेरीटेज पर गर्व करता है आज का न्यू इंडियाः राजनाथ सिंह

उदयपुर, 02 जनवरी। देश की समृद्ध सभ्यतागत विरासत की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि आधुनिक भारत अपने प्राचीन अतीत और सांस्कृतिक परंपराओं को मान्यता देकर शक्ति और गौरव प्राप्त करता है। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के 104वें स्थापना दिवस समारोह को उदयपुर में संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता ने विज्ञान, चिकित्सा, गणित, व्याकरण, दर्शन और नैतिकता जैसे विभिन्न विषयों में ज्ञान प्रणालियों में भारत के स्थायी योगदान पर प्रकाश डाला।

सिंह ने कहा कि आज का भारत अपने अतीत पर गर्व करता है। आज का भारत अपनी परंपराओं का सम्मान करता है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को महत्व देता है। भारत की धरती ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट, ब्रह्मगुप्त, माधव, पाणिनी, पतंजलि, नागार्जुन, पिंगला, मैत्रेयी, गार्गी और तिरुवल्लुवर जैसे विद्वानों को जन्म दिया है। राजनाथ सिंह ने मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समर्पित देशभक्त बताया। उन्होंने कहा कि महाराणा भूपाल जी ने चित्तौड़ में हिंदू विश्वविद्यालय, उदयपुर में कृषि महाविद्यालय और बालिका शिक्षा सहित कई विद्यालयों की स्थापना की।

राजनाथ सिंह ने कहा कि मित्रों, इस संस्थान का नाम मेवाड़ के महाराणा श्री भूपाल सिंह जी के नाम पर रखा गया है। महाराणा श्री भूपाल सिंह जी केवल एक शासक ही नहीं थे; मुझे बताया गया है कि वे एक शिक्षाविद भी थे। उन्होंने चित्तौड़ में हिंदू विश्वविद्यालय, उदयपुर में कृषि महाविद्यालय और कई अन्य विद्यालयों की स्थापना की।

भीषण सर्दी में भी अडिग है देश की सुरक्षा, राजधानी से लेकर सीमाओं तक जवानों का हौसला कायम

नई दिल्ली। देश के एक बड़े हिस्से में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक तापमान लगातार गिर रहा है। ऐसे मौसम में जब आम लोग घरों में कंबलों के भीतर दुबकने को मजबूर हैं, तब भी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों में डटे हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी से लेकर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और बर्फ से ढकी पहाड़ियों तक, सुरक्षा बलों का जज्बा इस भीषण ठंड में भी कमजोर नहीं पड़ा है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो सुबह तड़के कड़कड़ाती ठंड के बीच 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी है। India Gate के आसपास घना कोहरा और सर्द हवाओं के बीच CRPF के जवान पूरे अनुशासन के साथ परेड अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। ठंड से बेपरवाह, सीना तान कर कदमताल करते जवान यह संदेश दे रहे हैं कि देश की आन बान शान के सामने मौसम की कोई अहमियत नहीं। इन दृश्यों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सुबह की सर्द हवाओं और कोहरे के बीच जवान लगातार अभ्यास में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर, उत्तर भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी हालात आसान नहीं हैं।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को बड़ी राहत, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में मिली जमानत

छत्तीसगढ़, 02 जनवरी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ में कथित उत्पाद शुल्क घोटाले के संबंध में जमानत दे दी है। यह राहत प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज दोनों मामलों में दी गई है। कोर्ट से जमानत फाइनल चार्जशीट दाखिल होने के बाद मिली है। हाल ही में ईडी ने शराब घोटाले में फाइनल चार्जशीट दाखिल की थी।

चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस घोटाले में कथित तौर पर राज्य के खजाने को 2,161 करोड़ से अधिक का चूना लगाया गया था। एजेंसी उन्हें इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताती है, जिसमें कथित तौर पर रिश्वतखोरी, ऑफ-द-बुक बिक्री और लाइसेंस में हेराफेरी का एक नेटवर्क शामिल था। यह कथित घोटाला छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के माध्यम से संचालित होता था, जहाँ शराब बनाने वालों से अनुकूल बाजार पहुँच के बदले कथित तौर पर रिश्वत ली जाती थी।

ईडी का कहना है कि सरकारी दुकानों के माध्यम से देशी शराब अवैध रूप से बेची जाती थी और विशिष्ट लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए विदेशी शराब के लाइसेंस (FL-10A) में हेराफेरी की जाती थी। इस मामले में कई अन्य हाई-प्रोफाइल नाम भी शामिल हैं, जैसे व्यवसायी अनवर ढेबर, पूर्व नौकरशाह अनिल टुटेजा और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जिन पर नियमित रूप से रिश्वत लेने का आरोप है। अब तक, ईडी इस मामले में 205 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुका है।

दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को करीब 200 से 250 करोड़ रुपये मिले हैं।

उन्होंने इस पैसे का उपयोग अपने रियल स्टेट के कारोबार में लगाया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की टीम ने चैतन्य बघेल के अलावा कई सीनियर आईएस अधिकारी, राजनेता और करोबारियों को भी गिरफ्तार किया है।

मथुरा में कार पलटने से एक छात्र की मौत, चार अन्य घायल

मथुरा। मथुरा जिले में कार पलटने से एक छात्र की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह घटना बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे कोतवाली क्षेत्र में नवादा गांव के पास की है जब कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर निवासी दर्श उर्फ संभव यादव (19) अपने चार दोस्तों के साथ पार्टी करके कार से घर लौट रहा था। उसने बताया कि तभी आगे चल रहे ट्रक चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के कारण यादव अपने वाहन से नियंत्रण खो बैठा।पुलिस ने बताया कि कार अनियंत्रित होकर पलट गई। रिफाइनरी क्षेत्र की पुलिस उपाधीक्षक श्वेता वर्मा ने बताया कि कार में सवार सभी लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने संभव को मृत घोषित कर दिया।

गिग-वर्कर्सः डिजिटल सुविधा की चकाचौंध में पसीने का अंधेरा

-ललित गर्ग

ऑनलाइन बाजार और त्वरित सेवाओं के इस दौर में गिग-वर्कर्स शहरी जीवन-व्यवस्था की वह अदृश्य रीढ़ बन चुके हैं, जिनके बिना दस मिनट में डिलीवरी और एक क्लिक पर सुविधा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बाजार आने-जाने के झंझट से लोगों को मुक्त करने वाले ये युवा हर मौसम, हर समय और हर जोखिम में घर-घर सामान पहुँचाते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जिनके श्रम पर डिजिटल अर्थव्यवस्था की ऊँची इमारत खड़ी है, वही श्रमिक सबसे अधिक असुरक्षा, शोषण और उपेक्षा झेल रहे हैं। नये साल की पूर्व संध्या पर गिग-वर्कर्स द्वारा की गई हड़ताल ने भले ही देशव्यापी आपूर्ति-श्रृंखला को ठप न किया हो, लेकिन इसने उनकी बदहाल कार्य-परिस्थितियों की ओर देश का ध्यान अवश्य खींचा है। यह हड़ताल किसी राजनीतिक उकसावे का परिणाम नहीं, बल्कि लगातार बढ़ते काम के दबाव, घटते मेहनताने, नौकरी की अनिश्चितता और सम्मान के अभाव की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी।

अपना व परिवार का पोषण करने वाले इन युवा गिग-वर्कर्स को अकसर सरपट दौड़ती मोटरसाइकिलों पर, भारी थैलों के साथ ऊँची इमारतों की सीढ़ियाँ चढ़ते देखा जा सकता है। समय सीमा का दबाव इतना तीव्र होता है कि जरा-सी देरी पर आर्थिक दंड झेलना पड़ता है। दुर्घटना, बीमारी या तकनीकी गड़बड़ी-किसी भी स्थिति में उनकी आय पर सीधा असर पड़ता है। ग्राहकों का व्यवहार भी प्रायः असंवेदनशील होता है। देर होने पर झिड़कियाँ, सामान में कमी निकालकर अपमान, कभी-कभी हिंसक व्यवहार और रेटिंग के जरिये भविष्य की कमाई पर प्रहार-यह सब इनके रोजमर्रा का हिस्सा है। इसके बावजूद औसतन 12-14 घंटे काम करने के बाद भी सात-आठ सौ रुपये की आय और वह भी बिना समुचित बीमा या सामाजिक सुरक्षा के एक गहरे शोषण की ओर इशारा करती है। गिग वर्कर्स वे लोग होते हैं जो पारंपरिक नौकरी के बजाय अस्थायी, लचीले और स्वतंत्र रूप से छोटे-छोटे काम (गिग्स) करते हैं, जो अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ऊबर, स्वीगी, जोमाटोज या अन्य ऐप्स के जरिए

मिलते हैं और इन्हें प्रति कार्य या प्रोजेक्ट के हिसाब से भुगतान मिलता है, न कि नियमित वेतन. इन श्रमिकों के पास कोई स्थायी रोजगार अनुबंध नहीं होता और वे खुद के बॉस की तरह काम करते हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक सुरक्षा (जैसे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन) जैसे लाभ नहीं मिलते। गिग वर्कर्स की चुनौतियाँ एवं मजबूरियां ज्यादा है, आय कम। आय की अनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा लाभों (जैसे बीमारी, दुर्घटना, पेंशन) का अभाव, श्रम अधिक-भुगतान कम, कामकाजी घंटों और मजदूरी को लेकर अक्सर विवाद। गिग वर्कर्स गिग इकॉनमी का हिस्सा हैं, जहाँ वे अपनी मर्जी से छोटे-छोटे, अस्थायी काम करके पैसे कमाते हैं, जो पारंपरिक 9-से-5 की नौकरी से अलग होता है। गिग वर्कर का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो आमतौर पर सेवा क्षेत्र में एक स्वतंत्र ठेकेदार या फ्रीलांसर के रूप में अस्थायी काम करता है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों से कमाई करता है। निस्संदेह, गिग अर्थव्यवस्था ने रोजगार सृजन की अपनी क्षमता दिखाई है। आज भारत में गिग-वर्कर्स की संख्या सवा करोड़ से अधिक है और अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या दो करोड़ पैंतीस लाख तक पहुँच सकती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बेरोजगारी के बढ़ते दौर में पढ़े-लिखे युवा इस व्यवस्था में विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि ह्यमजबूरीह्व में प्रवेश कर रहे हैं। जिस देश को युवाओं का देश कहा जाता है, वहाँ शिक्षित युवाओं का अस्थायी, असुरक्षित और सम्मानहीन श्रम-व्यवस्था में फँसना न केवल चिंताजनक, बल्कि शर्मनाक भी है। यह स्थिति बताती है कि हमारी विकास-नीतियाँ रोजगार की गुणवत्ता पर नहीं, केवल संख्या पर केंद्रित हैं। गिग-वर्कर्स की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कंपनियाँ उनसे पूरा काम लेती हैं, लेकिन उन्हें पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के दायरे में स्वीकार नहीं करतीं। उन्हें स्वतंत्र कामगार कहकर नियुक्ति, स्थायित्व, बीमा और न्यूनतम वेतन जैसी जिम्मेदारियों से बचा जाता है।

हायर एंड फायर की नीति, एल्गोरिदम आधारित नियंत्रण, रेटिंग सिस्टम और प्रोत्साहन के नाम पर लालच-ये सब मिलकर एक ऐसी अदृश्य जकड़न पैदा करते हैं, जिसमें श्रमिक स्वतंत्र दिखता है, लेकिन वास्तव में पूरी तरह नियंत्रित होता है। हड़ताल के दौरान भी अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर या ऑर्डर बढ़ाकर श्रमिक एकता को कमजोर कर दिया जाता है। 31 दिसंबर को एक प्रमुख खाद्य वितरण कंपनी द्वारा रिकॉर्ड ऑर्डर दर्ज किया जाना इसी विडंबना को उजागर करता है। हाल के दिनों में संसद में भी गिग-वर्कर्स के शोषण का मुद्दा उठा है। सांसद राघव चड्ढा और मनोज कुमार झा जैसे नेताओं ने इस वर्ग की दयनीय स्थिति पर ध्यान दिलाया है। यह स्वागतयोग्य है, क्योंकि नीति-निर्माण की प्रक्रिया में जब तक इन श्रमिकों की आवाज शामिल नहीं होगी, तब तक सुधार अधूरे रहेंगे। भारत सरकार द्वारा हालिया श्रम सुधारों में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। एग्रीगेटर कंपनियों के टर्नओवर का एक से दो प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान, आधार से जुड़े सार्वभौमिक खाता नंबर जैसी व्यवस्थाएँ एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रावधान वास्तव में गिग-वर्कर्स के जीवन में ठोस बदलाव ला पाएँगे? या फिर ये केवल कागजी सुधार बनकर रह जाएँगे? जब तक न्यूनतम आय, कार्य-घंटों की सीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होती, तब तक इन सुधारों को परिवर्तनकारी नहीं कहा जा सकता।

31 दिसंबर की हड़ताल भले ही पूरी तरह सफल न रही हो, लेकिन वह नैतिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह जायज थी। यह हड़ताल व्यवस्था को बाधित करने से अधिक, व्यवस्था के भीतर छिपे अन्याय, शोषण की वृत्ति एवं दोगलेपन को उजागर करने का प्रयास थी। गिग-वर्कर्स ने यह संदेश दिया कि वे केवल डिलीवरी बॉय नहीं, बल्कि श्रमशील नागरिक हैं, जिनके अधिकारों की अनदेखी अब और नहीं की जा सकती। निश्चित ही डिजिटल अर्थव्यवस्था का भविष्य गिग-वर्कर्स के बिना संभव नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि नीति-निमार्ता, कंपनियाँ और उपभोक्ता-तीनों अपनी भूमिका पर आत्ममंथन करें। कंपनियों को लाभ के साथ जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी, सरकार को कानूनों का सख्त क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा और उपभोक्ताओं को सुविधा के साथ संवेदनशीलता भी अपनानी होगी। यदि हम गिग-वर्कर्स को केवल सुविधा का साधन मानते रहे और उन्हें सम्मान, सुरक्षा व स्थायित्व नहीं दिया, तो यह केवल श्रमिकों का नहीं, बल्कि हमारी विकास-कल्पना का भी संकट होगा। विकसित भारत, उन्नत भारत एवं समृद्ध भारत के नाम पर एक बदनुमा दाग होगा। डिजिटल भारत की असली परीक्षा यही है कि वह अपने सबसे तेज दौड़ने वाले श्रमिकों को कितना सुरक्षित और सम्मानित जीवन दे पाता है। तेजी से फैलती ऑनलाइन सेवाओं की दुनिया में गिग-वर्कर्स की कार्य-सेवाओं को अब अनौपचारिक नहीं, बल्कि नियोजित, मान्यताप्राप्त और सम्मानजनक श्रम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उनकी मेहनत का उचित और सुनिश्चित भुगतान, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ और सामाजिक सुरक्षा कोई दया नहीं, बल्कि उनका अधिकार है, जिसमें सरकार को निर्णायक हस्तक्षेप करना ही होगा। मुनाफे की अंधी दौड़ में लगी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को यह समझना होगा कि श्रम केवल लागत नहीं, बल्कि व्यवस्था की आत्मा है; शोषण की मानसिकता छोड़कर संवेदनशीलता और जवाबदेही अपनाए बिना कोई भी डिजिटल विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। यदि गिग-वर्क को गरिमा, सुरक्षा और स्थायित्व के साथ विकसित किया जाए, तो यही सेवाएँ मजबूरी का प्रतीक नहीं, बल्कि रोजगार की एक आदर्श और मानवीय व्यवस्था बन सकती हैं, जहाँ सुविधा केवल उपभोक्ता को नहीं, सम्मान कामगार को भी मिले।

ईरानी बहनें तोड़ रही बुर्का की जंजीरे, भारत में बढ़ रही है कट्टरता

-संजय सक्सेना

ईरान में इस्लामिक शासन के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का साहसी विद्रोह पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है, जहां कुरान के नाम पर थोपी गई बुर्का और नकाब जैसी परंपराओं के खिलाफ सड़कों पर आवाज उठ रही है। खामेनेई की तानाशाही वाली सरकार के सामने ईरानी महिलाएं बिना नारे लगाए, बिना हिंसा किए, बस सिर से दुपट्टा उतारकर सड़कों पर उतर आई हैं, जो महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद 2022 से चला आ रहा आंदोलन अब 2025-2026 में और तेज हो गया है। यह बगावत न केवल ईरान तक सीमित है, बल्कि अरब और अन्य मुस्लिम देशों में भी बुर्का हटाने की हवा चल रही है, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत जैसे स्थानों पर इसके पक्ष में कट्टरता बढ़ रही है। यह और बात है कि इन देशों के मुसलमानों को अरब जगत मुस्लिम मानने को ही नहीं तैयार होता है।

गौरतलब हो, ईरान को पूरी तरह इस्लामिक राष्ट्र कहा जाता है, जहां 1979 की क्रांति के बाद अयातुल्लाह खुमैनी ने कुरान आधारित शासन स्थापित किया और महिलाओं पर सख्त हिजाब अनिवार्य कर दिया। नैतिक पुलिस द्वारा सड़कों पर गश्त कर महिलाओं को पकड़ना और सजा देना आम हो गया, लेकिन 2022 में 22 वर्षीय महसा अमीनी की हिरासत में संदिग्ध मौत ने चिंगारी जला दी। उसके बाद लाखों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर दुपट्टा जलाया, बाल कटवाए और नारे लगाए, जिससे पूरे देश में आंदोलन फैल गया। हालिया समाचारों के अनुसार, दिसंबर 2025 में तेहरान और अन्य शहरों में महिलाएं खुलेआम बिना दुपट्टे के घूम रही हैं, जो सरकार को डरा रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने विवादास्पद हिजाब कानून को स्थगित कर दिया, लेकिन सर्वोच्च नेता खामेनेई के दबाव में सैन्य बल तैनात हैं। प्रदर्शनों में कम से कम छह मौतें हो चुकी हैं और दर्जनों गिरफ्तारियां हुई हैं, फिर भी महिलाओं का खामोश विरोध जारी है।

बहरहाल, यह आंदोलन सिर्फ ईरान का नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर इस्लाम के नाम पर थोपी गई कट्टरता के खिलाफ जागृति का प्रतीक है। अरब प्रायद्वीप से इस्लाम फैला, लेकिन अब सऊदी अरब जैसे देशों में महिलाओं को पहले से अधिक स्वतंत्रता मिल रही है, जहां अब पूर्ण बुर्का अनिवार्य नहीं। मध्य एशिया के मुस्लिम बहुल देशों में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। कजाकिस्तान, जहां 70 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है, ने 2025 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का-नकाब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जुमार्ना 10 हजार से एक लाख रुपये तक। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने पहले ही चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर रोक लगा रखी है, ताकि धार्मिक कट्टरपंथ न फैले। कुल 16 से अधिक देशों ने बुर्का या नकाब पर कानूनी पाबंदी लगा दी है। यूरोपीय देशों में स्विट्जरलैंड ने 2021 के जनमत संग्रह में 51.21 प्रतिशत वोटों से 2025 में इसे लागू किया, जबकि फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, बुल्गारिया, इटली और जर्मनी ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर जुमार्ना या जेल की सजा निर्धारित की। बेल्जियम में मात्र 300 महिलाएं ही बुर्का पहनती थीं, फिर भी 10 लाख मुसलमानों के बीच इसे प्रतिबंधित किया गया।

इसके विपरीत, दक्षिण एशिया में स्थिति उलटी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में, जहां इस्लाम स्थानीय रूप से फैला, वहां कट्टरता बढ़ रही है। भारत के बिहार में हाल ही में नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला डॉक्टर का दुपट्टा हटाने पर विवाद हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान तक से विरोध के सुर उठे। बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि बुर्का पसंद है तो पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाएं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में महिलाएं दुपट्टा या बुर्का पहनने को धार्मिक अधिकार बताकर प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि वहां के सर्वेक्षणों में 60-70 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं इसे स्वैच्छिक बताती हैं, लेकिन कट्टर समूह दबाव बनाते हैं। भारत में कर्नाटक हिजाब विवाद के बाद स्कूल-कॉलेजों में बहस चली, जहां मुस्लिम छात्राओं ने पहनने पर जोर दिया। यह विरोधाभास दशार्ता है कि जहां मूल इस्लामिक केंद्रों में महिलाएं आजादी चाह रही हैं, वहीं यहां आयातित कट्टरता बुर्का को मजबूरी बना रही है।

सऊदी अरब में भी महिलाएं ड्राइविंग और बिना नकाब के घूमने की मांग कर रही हैं। लेकिन दक्षिण एशिया में तस्वीर उलट है। यहां बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में मुस्लिम महिलाएं उसी हिजाब या बुर्का को धार्मिक फर्ज बताकर प्रदर्शन कर रही हैं। पाकिस्तान में हाल ही में लाहौर और कराची की सड़कों पर महिलाओं ने जुलूस निकाले। वे कह रही हैं कि स्कूलों में हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है। वहां के सर्वे बताते हैं कि साठ से सत्तर प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं इसे अपनी मर्जी से पहनती हैं। लेकिन कट्टर गुट दबाव बनाते हैं। पड़ोसियों की नजरें, मौलवियों की फतवे और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से कई लड़कियां मजबूर हो जाती हैं। बांग्लादेश में ढाका विश्वविद्यालय के परिसरों में छात्राओं ने हिजाब अनिवार्य करने की मांग की। वहां भी तहरीक-ए-तालिबान जैसे संगठन पीछे हैं। महिलाएं कहती हैं कि बिना हिजाब के पढ़ाई नहीं करेंगी। लेकिन गुप्त सर्वेक्षणों में पता चलता है कि आधी से ज्यादा लड़कियां इसे बोझ मानती हैं। फिर भी भीड़ का दबाव उन्हें चुप करा देता है।

भारत में कर्नाटक का हिजाब विवाद तो चरम पर पहुंच गया। उडुपी के कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं ने कक्षा में घुसने से इनकार कर दिया। वे दुपट्टा या हिजाब के बिना परीक्षा नहीं देंगी, ऐसा हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों के पीछे जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसे संगठन थे। कोर्ट ने फैसला दिया कि यूनिफॉर्म का पालन जरूरी है, लेकिन बहस थम नहीं रही। मंड्या, बीदर जैसे जिलों में स्कूलों के बाहर जुलूस हुए। छात्राओं के माता-पिता भी सड़क पर उतरे। वे चिल्ला रहे थे- हमारी बेटियों का धर्म सुरक्षित रखो। लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रामीण इलाकों में कई लड़कियां डर से हिजाब पहनती हैं। पड़ोस के हिंदू-मुस्लिम तनाव में इसे ढाल बना लिया जाता है।

उक्त देशों में यह प्रवृत्ति चिंताजनक है। जहां दुनिया महिलाओं को सशक्त बना रही है, वहां दक्षिण एशिया में कट्टरता उन्हें पुराने जंजीरों में जकड़ रही। सर्वे बताते हैं कि ज्यादातर महिलाएं स्वतंत्रता चाहती हैं। लेकिन अल्पसंख्यक कट्टर गुट बहुमत को दबा रहे हैं। क्या यह धार्मिकता है या राजनीति? नेताओं को चाहिए कि वे तथ्यों पर ध्यान दें। महिलाओं को चुनाव दें- पहनें या न पहनें। तब सच्ची तस्वीर सामने आएगी। अन्यथा यह आयातित आग स्थानीय संस्कृति को भस्म कर देगी। दक्षिण एशिया की महिलाओं को मूल आजादी मिलनी चाहिए, न कि मजबूरी।

बात ईरान में आए बदलाव की कि जाए तो इसके पीछे गहन कारण हैं। ईरान जैसे देशों में आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी ने महिलाओं को जागृत किया, जहां प्रदर्शनों में आजीविका की मांगें भी जुड़ गईं। मुस्लिम बहुल देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा को बहाना बनाकर बुर्का प्रतिबंध बढ़ा, क्योंकि चेहरा ढका होना अपराध को आसान बनाता है। वैश्विक स्तर पर 16 देशों के प्रतिबंध से संदेश साफ है कि बुर्का महिलाओं के उत्पीड़न का प्रतीक माना जा रहा। दक्षिण एशिया में कट्टरता का कारण विदेशी धन-सहायता और राजनीतिक उन्माद है, जहां बांग्लादेश-पाकिस्तान में मदरसों से प्रेरित युवतियां बुर्का को पहचान बना रही हैं। ईरानी महिलाओं की बगावत ने दुनिया को दिखाया कि इस्लाम के नाम पर थोपी गई परंपराएं टूट रही हैं। यदि यह लहर फैली, तो कट्टरता वाले क्षेत्रों में भी परिवर्तन अपरिहार्य होगा। आंकड़ों से सिद्ध है कि जहां प्रतिबंध लगे, वहां महिलाओं की भागीदारी 20-30 प्रतिशत बढ़ी है। यह संघर्ष स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

अरावली पर सरकार की मंशा आखिर क्या थी?

-निरंजन परिहार

अरावली बचाओ अभियान की जीत हुई। सरकार की सलाह पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की 100 मीटर तक ऊंचाई की पहाड़ियों को अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा न मानने का फैसला दिया था। इस मामले पर सरकार के विरोध में शुरू हुए तेज आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही आदेश पर रोक लगा दी गई है। इस निर्णय को अरावली बचाओ आंदोलन की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे अरावली के संरक्षण के लिए और समय मिल गया है। माना कि अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देकर जनता की चिंताओं को गंभीरता से लिया है। लेकिन संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि यह सत्य अभी सार्वजनिक होना बाकी है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, अरावली की 100 मीटर की पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा ही न मानने की सिफारिश किस मंशा से की थी?

सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 को अरावली पहाड़ियों से जुड़े एक अहम फैसले में 20 नवंबर के अपने पिछले आदेश पर रोक लगा दी। इस पिछले आदेश में कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई 100 मीटर ऊंचाई के आधार पर अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा को स्वीकार किया था। लेकिन 29 दिसंबर को तीन जजों की बेंच ने इस नई परिभाषा पर सीधे कार्रवाई करने से पहले गहन समीक्षा की जरूरत बताई। कोर्ट ने यह भी कहा कि 100 मीटर नियम का व्यापक प्रभाव समझे बिना उसे लागू नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कहा कि एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जो परिभाषा, ऊंचाई के मानदंड और खनन की संभावित अनुकूलता पर अध्ययन करे।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत सहित पार्टी नेताओं ने इस फैसले को जनता की आवाज की जीत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सही कदम के रूप में देखा। गहलोत ने आम तौर पर इस मुद्दे पर कहा कि अरावली रेंज को कमजोर करने वाली परिभाषा पर्यावरण और स्थानीय जीवन के लिए जोखिम भरी थी। उन्होंने अदालत द्वारा अपने ही फैसले को रोकने को लोगों की संवेदनशीलता को सम्मान देने वाला फैसला बताते हुए कहा कि वर्तमान पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए यह बेहद आवश्यक है कि अरावली को लेकर अगली शताब्दी तक की स्थिति को सोचकर काम किया जाए। गहलोत ने इस मुहिम में जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री को भी अब पर्यावरण के हित में काम करने की सोच रखनी चाहिए। सरिस्का सहित पूरे अरावली में खनन बढ़ाने की सोच भविष्य के लिए खतरनाक है। गहलोत मानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण पर जनता की चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए।

विशेषज्ञों का कहना था कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली महत्वपूर्ण पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो सकती थीं, जिससे खनन और पर्यावरणीय क्षरण बढ़ सकता था। पर्यावरण प्रेमियों और आन्दोलनकारियों ने इसे आरंभ से ही अरावली के अस्तित्व के लिए खतरा बताया। कई विशेषज्ञों ने कहा कि अगर 100 मीटर मानदंड लागू होता तो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जमीनें अलग हो जाएंगी और उन्हें खनन और अवैध गतिविधियों के लिए खोल दिया जाएगा। 29 दिसंबर के फैसले पर प्रमुख पर्यावरणवादी और आंदोलन से जुड़े लोग इसे एक बड़ी जीत और न्याय का प्रतीक मानते हैं। उनका मानना है कि इस फैसले से यह संदेश गया है कि संरक्षण को केवल तकनीकी परिभाषा के आधार पर कमजोर नहीं किया जा सकता। कई ने कहा कि अदालत ने जनता की आवाज और वैज्ञानिक चिंताओं को सही ढंग से समझा है।

अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है जो गुजरात से दिल्ली तक लगभग 690 किमी में फैली हुई है और यह उत्तर-पश्चिम भारत के पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह भूजल रिचार्ज, धूल के तूफानों को रोकने, जैव विविधता और स्थानीय जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती है। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई 100 मीटर की नई परिभाषा ने पूरी अरावली को ही खतरे में डाल दिया, क्योंकि इसके तहत कम ऊंचाई वाली लगभग 90% पहाड़ियों को अरावली के दायरे से बाहर किया जा सकता था। जिससे वे इलाके खनन और निर्माण के लिए खोले जा सकते थे। इस फैसले के विरोध में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में अरावली बचाओ अभियान शुरू हुआ। राजस्थान में स्तर पर, इस मुद्दे को उठाया गया, इस व्यापक समर्थन ने जन आंदोलन का रूप धर लिया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले को रोकना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट के 29 दिसंबर के फैसले के बाद केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को लंबे समय से उठ रहे विवाद का समाधान ढूंढना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति गठित करने की बात कही है, जिसका मुख्य काम होगा कि अरावली की वास्तविक परिभाषा, ऊंचाई मानदंड और संरक्षण खतरे पर वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाए। सरकार अब अदालत के निर्देश के अनुसार नए नियमों को लागू करने से पहले वैज्ञानिक जांच और विशेषज्ञ रिपोर्ट तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। पर्यावरण मंत्री ने संकेत दिए हैं कि कोई भी नया खनन पट्टा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक एक व्यापक और स्थायी प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाती। अवैध खनन पर सरकार की रुख भी और अधिक कड़ी होने की उम्मीद है। हाल के समय में जैसे कुछ सरकारी निदेशों में पूरे अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज नहीं दी जाएगी जैसी बातें सामने आई हैं, यह संकेत है कि खनन पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण प्राथमिकता बनेगा। अरावली बचाओ अभियान की सफलता लोकतंत्र, पर्यावरण चेतना और जनसहभागिता की प्रभावी मिसाल बन गई है। अदालत का फैसला यह भरोसा देता है कि कानून व्यवस्था पर्यावरणीय संवेदनशीलता को समझती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संघर्ष समाप्त हो गया, बल्कि इसका मतलब है कि अब संघर्ष ठोस नीति, वैज्ञानिकता और पारदर्शिता की मांग करेगा। अरावली सिर्फ राजस्थान की नहीं, यह उत्तर भारत की प्रकृति की रीढ़ है। जनता की एकजुटता से सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि अगर अरावली बची रहेगी, तो ही रेगिस्तान की रेत शहरों तक नहीं पसरेगी, उत्तर भारत की हवाओं सहित जल का भविष्य सुरक्षित रहेगा और जनजीवन निखरेगा। इसी वजह से, अरावली पर यह फैसला आने वाले समय में देश की अन्य पर्यावरणीय लड़ाइयों के लिए भी दिशा तय कर सकता है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

नये साल में ट्रेंडिंग स्टार खेसारीलाल यादव की बुलबुल बनी बिग बॉस 19 फेम नीलम गिरी

भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारीलाल यादव ने नये साल 2026 की शुरूआत धमाकेदार अंदाज में की है। उनका नया गाना बुलबुल आज रिलीज होते ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर छा गया। रिलीज के कुछ ही घंटों के भीतर इस गाने ने लाखों व्यूज हासिल कर लिए, जो खेसारीलाल यादव की जबरदस्त लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग को साफ दशार्ता है। नववर्ष के मौके पर आए इस गाने को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। इस गाने की सबसे बड़ी खासियत है बिग बॉस 19 फेम अभिनेत्री नीलम गिरी की मौजूदगी, जो ह्नबुलबुलह्व के किरदार में नजर आ रही हैं। खेसारीलाल यादव और नीलम गिरी की केमेस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। दोनों की जोड़ी स्क्रीन पर नई ऊर्जा, ताजगी और रोमांटिक अंदाज के साथ नजर आती है, जिसने गाने को और भी खास बना दिया है। गाने का म्यूजिक और विजुअल ट्रीट युवाओं के बीच तेजी से ट्रेंड कर रहा है। बुलबुल को सुर म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया है। गाने को खेसारीलाल यादव और शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसके बोल छोटू यादव ने लिखे हैं। संगीत आर्या शर्मा का है, जिसने गाने को आधुनिक और कैची टच दिया है। कंपोज़िशन रौशन सिंह, मिक्स-मास्टर जीतू शर्मा और डीआई रोहित सिंह ने किया है, जिससे गाना तकनीकी रूप से भी बेहद मजबूत बन पड़ा है। खेसारीलाल यादव ने गाने को लेकर कहा कि बुलबुल नए साल की उमंग और सकारात्मक ऊर्जा को दशार्ता है। उन्होंने अपने चाहने वालों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दर्शकों का प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। खेसारी ने यह भी उम्मीद जताई कि यह गाना लोगों के दिलों में खास जगह बनाएगा और लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

मूल राष्ट्रवादी चेतना, लोकतंत्र और अधिनायकवाद के प्रति सतर्कता

संजीव ठाकुर

राष्ट्रवाद आधुनिक राष्ट्र-राज्य की वैचारिक आधारशिला है। यह केवल भौगोलिक सीमाओं या राजनीतिक सत्ता से संबद्ध अवधारणा नहीं है, बल्कि साझा इतिहास, सांस्कृतिक स्मृति, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक उत्तरदायित्वों का समन्वित स्वरूप है। राष्ट्रवाद का मूल चरित्र सार्वभौमिक और समावेशी होता है, जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और मानवीय गरिमा जैसे मूल सिद्धांतों को पुष्ट करता है। ऐतिहासिक रूप से यह सिद्ध हुआ है कि राष्ट्र-निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया में राष्ट्रवादी चेतना की भूमिका निर्णायक रही है। किंतु जब यही चेतना सत्ता-केंद्रित राजनीति, संकीर्ण वैचारिक आग्रहों और तात्कालिक राजनीतिक लाभों से संचालित होने लगती है, तब यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है।

लोकतांत्रिक राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक का यह नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि वह राष्ट्र के प्रति निष्ठावान और सजग रहे। किंतु इस निष्ठा का आशय अंध-समर्थन या आलोचनात्मक विवेक का त्याग नहीं है। दुर्भाग्यवश, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रवाद को धर्म, जाति और संप्रदाय के साथ जोड़कर सत्ता-प्राप्ति का साधन बनाए जाने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ी है। ऐसी राजनीति न केवल राष्ट्रीय एकता को खंडित करती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता और निष्पक्षता को भी कमजोर करती है। इतिहास साक्षी है कि सत्ता के दीर्घकालिक केंद्रीकरण ने राजाओं, सम्राटों और शासकों को निरंकुश बनाया है। आधुनिक लोकतंत्र में भी यह खतरा कम नहीं हुआ है, बल्कि अधिक परिष्कृत रूप में उपस्थित है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत सत्ता का निरंतर आवर्तन है। सत्ता का परिवर्तनशील होना शासन को उत्तरदायी, पारदर्शी और जनोन्मुख बनाता है। इसके विपरीत, जब सत्ता लंबे समय तक एक ही राजनीतिक शक्ति के अधीन रहती है, तो अधिनायकवादी प्रवृत्तियों का उदय स्वाभाविक हो जाता है। अवसरवादी राजनीति, पद-लोलुपता और जातिगत समीकरणों का अतिवादी प्रयोग लोकतांत्रिक संतुलन को बिगाड़ देता है। इस प्रक्रिया में जनता को दूरगामी राष्ट्रीय हितों के स्थान पर तात्कालिक लाभों के प्रलोभन में उलझाया जाता है, जिससे नीति-निर्माण की गुणवत्ता और राष्ट्रीय विकास की क्षमता दोनों प्रभावित होती हैं।

लोकतंत्र में राजनीति का उद्देश्य जनभावनाओं का शोषण नहीं, बल्कि उनका संरक्षण और संवर्द्धन होना चाहिए। किंतु जब राजनीति का केंद्र बिंदु सत्ता-प्राप्ति और सत्ता स्थायित्व बन जाता है, तब सिद्धांतों की प्रतिबद्धता कमजोर पड़ जाती है। अवतारवाद, सस्ती लोकप्रियता और भावनात्मक ध्रुवीकरण लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर देते हैं। भारतीय राजनीतिक परंपरा में शाम, दाम, दंड, भेद को शासन के उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है, किंतु आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र में इनका अति प्रयोग अनुशासन, नैतिकता और संस्थागत विश्वास को क्षीण करता है। लोकप्रियता को मापने के सुदृढ़ लोकतांत्रिक उपकरणों के अभाव में कई बार संगठित किंतु संख्यात्मक रूप से छोटे समूह नीति-निर्माण पर विपरीत प्रभाव डालने लगते हैं। यह स्थिति बहुमत के शासन के लोकतांत्रिक आदर्श के विपरीत है। दलबदल, अवसरवादी गठबंधन और सिद्धांतहीन राजनीतिक व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण के प्रमुख कारण बन चुके हैं। भारतीय संविधान के भीतर विद्यमान कुछ प्रक्रियात्मक छिद्रों का उपयोग कर राजनीतिक दल सत्ता-संरक्षण के जटिल ताने-बाने बुनते हैं, जिनके दीर्घकालिक दुष्परिणाम समाज और राष्ट्र दोनों को भुगतने पड़ते हैं।. जातिवादी राजनीति और लोकप्रियता की व्यावहारिक मजबूरियों ने खाप पंचायतों जैसी समानांतर संरचनाओं को जन्म दिया है। ये संरचनाएँ पंचायती राज व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती हैं, जिससे लोकतंत्र की जमीनी संस्थाएँ कमजोर होती हैं। इसी प्रकार, धर्म और धार्मिक प्रथाओं में समानता तथा स्वतंत्रता का हनन तुष्टीकरण-आधारित राजनीति का प्रतिफल है। लोकतांत्रिक समाज में समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत किसी भी नीति-निर्णय के मूल में होने चाहिए। एकतरफा और भावनात्मक निर्णय इन मूल्यों के प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं।

अतिराष्ट्रवाद की अवधारणा, जब लोकतांत्रिक विवेक से विमुख हो जाती है, तब तानाशाही प्रवृत्तियों को वैधता प्रदान करने लगती है। सैनिक राष्ट्रवाद, भय की राजनीति और सस्ती लोकप्रियता ने बीसवीं शताब्दी में अनेक देशों में लोकतंत्र को क्षतिग्रस्त किया है। पाकिस्तान, म्यांमार और उत्तर कोरिया जैसे उदाहरण दशार्ते हैं कि सुरक्षा और राष्ट्रहित के नाम पर सैन्य या अधिनायकवादी नियंत्रण किस प्रकार लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। ये उदाहरण लोकतंत्र के लिए सतत चेतावनी के रूप में देखे जाने चाहिए।

लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य जनता का विश्वास अर्जित करना, उनकी सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। किंतु जब शासन सत्ताचरित्र, अवसरवाद और सत्ता में बने रहने की रणनीतियों में उलझ जाता है, तब लोकतंत्र के संस्थागत स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया कमजोर होने लगते हैं। ऐसे समय में समाज के प्रबुद्ध, सजग और जिम्मेदार वर्ग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि समय रहते विवेकपूर्ण हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो लोकतंत्र के दुरुपयोग के परिणाम दीर्घकालिक और विध्वंसकारी हो सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि तात्कालिक लोकप्रियता और अवसरवादी लाभों के स्थान पर संतुलित, समावेशी और बहुआयामी लोकतांत्रिक विकास को प्राथमिकता दी जाए। सरकार, राजनीतिक दल, मीडिया, सिविल सोसाइटी और नागरिक समाज—सभी को मिलकर संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सामाजिक संतुलन की रक्षा करनी होगी। यही समेकित प्रयास राष्ट्रवाद को उसकी मूल, मानवीय और उदात्त चेतना में पुनर्स्थापित कर सकता है तथा लोकतंत्र को अधिनायकवाद की संभावित खतरों से सुरक्षित रख सकता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कृष्णा कदम को नवक्षितीज महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार

मुंबई (उत्तरशक्ति)। नवक्षितीज चैरिटेबल ट्रस्ट, मुंबई की ओर से प्रदान किया जाने वाला राज्यस्तरीय नवक्षितीज महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2026 घोषित कर दिया गया है। यह सम्मान स्वास्थ्य, सामाजिक, शैक्षणिक, कला, क्रीड़ा और पत्रकारिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को प्रदान किया जाता है। इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार कदम कृष्णा मेडिकल सहायता कक्ष के प्रमुख कृष्णा कदम को देने की घोषणा की गई है। पुरस्कार वितरण समारोह 8 फरवरी 2026 को डॉ. नानुबेन नानावटी कारागृह, नंदादीप हाईस्कूल, गोरेगांव में आयोजित किया जाएगा।

बता दें कि कृष्णा कदम पिछले कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद मरीजों को शहर के बड़े अस्पतालों में त्वरित इलाज उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कदम कृष्णा मेडिकल सहायता कक्ष की स्थापना कर रक्तदान, मेडिकल सहायता, दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ-पैर उपलब्ध कराना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने जैसे सराहनीय कार्य किए हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उनके इस समर्पण और सामाजिक योगदान को देखते हुए नवक्षितीज चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उन्हें इस सम्मान से नवाजा जा रहा है।

इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से चयनित अन्य पुरस्कारार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिनमें प्रमुख रूप से मंगेश चिवटे (स्वास्थ्यदूत, करमाळा), संदीप ढवले (गोविंदा पथक प्रशिक्षक, मुंबई लगातार तीन बार 10 स्तरीय दहीहांडी निर्माण), यशवंत जाधव (कला क्षेत्र, संभाजीनगर), अनिल निर्मल (पत्रकारिता, मुंबई 26/11 हमले के दौरान घायल कैमरामैन), नामदेव पेदाम (सामाजिक क्षेत्र, नागपुर), संदीप भोईर (कला क्षेत्र, पालघर), अब्दुल मुनीफ (शैक्षणिक क्षेत्र, परभणी), गजानन भलावी (सामाजिक क्षेत्र, नाशिक), अंजली सपकाळे (सामाजिक क्षेत्र, मुंबई), हर्षल नवलकर (कला कौशल, चंद्रपुर), शशिकला जाधव (शैक्षणिक क्षेत्र, मुंबई), शरद मस्के (सामाजिक क्षेत्र, मुंबई), तुकाराम मोकल (कला क्षेत्र, मुंबई), सतीश महाजन (सामाजिक क्षेत्र, पनवेल) इन सभी विभूतियों को समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ह्नवक्षितीज महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा।

ललित माली की माताजी फूलीबाई माली का देहावसान, सैकड़ों लोगों ने दी अंतिम विदाई

पालघर(उत्तरशक्ति)। समाजसेवा और धार्मिक जीवन की मिसाल रहीं फूलीबाई पुखराज माली का मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 को लंबी बीमारी के बाद उनके पैतृक निवास रानी में निधन हो गया। वे राष्ट्रीय हिन्दू सेवा संघ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ललित माली की माताजी थीं। 31 दिसंबर 2025 को पूरे धार्मिक विधि-विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। रामस्नेही संप्रदाय से गहराई से जुड़ी फूलीबाई केवल भक्ति में विश्वास रखने वाली, सरल, सौम्य एवं धर्मनिष्ठ महिला थीं। जैतारण से पधारे सतगुरु संत श्री हजारीमलजी गेहलोत एवं अन्य रामस्नेही संतों की उपस्थिति में उनके निवास स्थान से मोक्षधाम तक गाजे-बाजे के साथ वैकुंठी यात्रा निकाली गई। वैकुंठी यात्रा में माली समाज सहित विभिन्न समाजों के सैकड़ों लोगों ने सहभागिता कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने पीछे छह पुत्र, तीन पुत्रियां तथा नाती-पोते से भरा-पूरा परिवार छोड़कर वे स्वर्ग सिधार गईं। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक एवं संवेदना का माहौल है।

ऑल-न्यू किआ सेल्टोस 10.99 लाख में लॉन्च

मुंबई। किआ इंडिया ने आज ऑल-न्यू किआ सेल्टोस की कीमतों की आधिकारिक घोषणा कर दी। 10.99 लाख (एक्स-शोरूम) की प्रारंभिक कीमत के साथ कंपनी ने मिड-एसयूवी सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को और मजबूत किया है तथा ग्राहकों के लिए अपनी पसंदीदा एसयूवी का स्वामित्व पाने का आकर्षक अवसर उपलब्ध कराया है। दूसरी पीढ़ी की इस बड़ी, अधिक सशक्त और उन्नत एसयूवी को व्यापक ग्राहक वर्ग तक पहुंचाकर किआ ने इस सेगमेंट के स्थापित मानकों को एक नई दिशा दी है। ऑल-न्यू किआ सेल्टोस आधुनिक भारतीय परिवारों और एसयूवी खरीदारों के लिए एक समग्र विकल्प के रूप में सामने आई है। यह वाहन स्पेस, आराम, सुरक्षा और एडवांस्ड तकनीक का संतुलित संयोजन प्रस्तुत करता है, वह भी अत्यंत प्रतिस्पर्धी कीमत पर। इस अवसर पर किआ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री ग्वांगु ली ने कहा, ऑल-न्यू सेल्टोस केवल एक नया मॉडल नहीं है, बल्कि उसी नाम की अगली महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसने भारत में किआ की यात्रा को दिशा दी। इस नई पीढ़ी के साथ हमारा उद्देश्य स्पष्ट है—स्पेस, सुरक्षा, तकनीक और स्वामित्व अनुभव के मानकों को नई ऊंचाई पर ले जाना और ग्राहकों को उत्कृष्ट मूल्य प्रदान करना। यह रणनीतिक कदम हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करेगा तथा ब्रांड के प्रति ग्राहकों के विश्वास को भी सुदृढ़ बनाएगा। भारत के इस महत्वपूर्ण एसयूवी सेगमेंट में गति और हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किआ पूरी तरह तैयार है।

बीएमसी चुनाव: एक गठबंधन ऐसा भी वीबीए को नहीं मिले उम्मीदवार

मुंबई। मुंबई में आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा है। प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) शहर में उसे आवंटित 16 सीटों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने में विफल रही है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के साथ सीट-बंटवारे की व्यवस्था के तहत, वीबीए को मुंबई में कुल 62 सीटें आवंटित की गई थीं। हालांकि, योग्य उम्मीदवारों की कमी और कई संभावित उम्मीदवारों के दस्तावेजों के अपूर्ण होने के कारण वीबीए इन 16 सीटों पर नामांकन दाखिल नहीं कर पाई। खबरों के मुताबिक, वीबीए ने कांग्रेस नेतृत्व को सूचित कर दिया है कि वह इन 16 सीटों पर चुनाव लड़ने में असमर्थ है और कांग्रेस इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इस घटनाक्रम के बाद, कांग्रेस ने मुंबई के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची मजबूत कर ली है।

अब तक, कांग्रेस ने मुंबई में 143 उम्मीदवारों की घोषणा की है। वीबीए 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा, गठबंधन की कुछ सीटें अन्य सहयोगी दलों जैसे वामपंथी समूहों और राष्ट्रीय समाज पार्टी (आरएसपी) को आवंटित की गई हैं।

जिलाधिकारी कार्यालय में पुस्तक पेटी भेंट अभियान का आयोजन

जिलाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड़ के हाथों स्कूलों को पुस्तक पेटियों का वितरण

पालघर (उत्तरशक्ति)। विद्यार्थियों में पठन-संस्कृति को बढ़ावा देने तथा उनके शैक्षणिक और बौद्धिक विकास को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कार्यालय, पालघर में पुस्तक पेटी भेंट अभियान का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड़ ने कहा कि पुस्तकें विद्यार्थियों के ज्ञान, विचार और व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नववर्ष के अवसर पर मराठी पठन-संस्कृति को और अधिक समृद्ध करने के उद्देश्य से यह अभियान मनोविकास ग्रंथोत्सव एवं पालघर साहित्य व कला प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान में तथा निऑन फाउंडेशन के विशेष सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड़ के शुभहस्ते संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में निवासी उपजिलाधिकारी सुभाष भागडे, तहसीलदार सचिन भालेराव, पालघर साहित्य व कला प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रकाश लवेकर, सचिव अमोल पाटकर, कोषाध्यक्ष राहुल ठाकुर, निऑन फाउंडेशन की संस्था पाटील, राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक प्रमोद पाटील सहित विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

इस अभियान के अंतर्गत पालघर जिले की जिला परिषद विद्यालय– रोडखड, दाभोण (पिलेना पाड़ा), टेम्भीखोडावे, घाटीम, कर्दल, आर्यन, अभिनव विद्यालय विराथन बुद्रुक तथा आंभाण-मनोर क्षेत्र की जिला परिषद एवं संस्थागत विद्यालयों को उपयोगी व पठनीय पुस्तकों से युक्त पुस्तक पेटियाँ वितरित की गईं। पुस्तक वितरण के दौरान जिलाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड़ ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि पुस्तक पेटियों को केवल अलमारियों में बंद न रखा जाए, बल्कि विद्यार्थियों को मुक्त रूप से पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया जाए। ऐसे उपक्रमों से विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि बढ़ेगी और उनका वैचारिक एवं बौद्धिक विकास निश्चित रूप से होगा।

भाजपा नेता वीरेंद्र दुबे अपक्ष ने नामांकन लिया वापस

मुंबई। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के महामंत्री एवं चांदीवली विधानसभा के पूर्व भाजपा अध्यक्ष (2012) एडवोकेट वीरेंद्र दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे साथ पार्टी द्वारा बार-बार अन्याय किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2012 में वीरेंद्र दुबे ने वार्ड क्रमांक 163 से टिकट की मांग की थी, लेकिन उन्हें टिकट न देकर सीताराम तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया। इसके बाद 2017 में उनकी दावेदारी वार्ड क्रमांक 159 से थी, किंतु तत्कालीन सांसद पूनम महाजन ने दूसरी पार्टी से आए प्रकाश मोरे को टिकट दिया, जो बाद में नगरसेवक बने।

वर्तमान चुनाव में भी वार्ड क्रमांक 159 से वीरेंद्र दुबे ने टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर प्रकाश मोरे को ही प्रत्याशी घोषित किया। लगातार उपेक्षा के बावजूद वीरेंद्र दुबे ने पार्टी अनुशासन का पालन करते हुए नेतृत्व के निर्णय को स्वीकार किया है।

सूत्रों के अनुसार, एडवोकेट वीरेंद्र दुबे आज अपना भरा हुआ अपक्ष (निर्दलीय) नामांकन फॉर्म वापस लिया।

इस निर्णय को चांदीवली क्षेत्र के उत्तर भारतीय कार्यकताओं में पार्टी अनुशासन और निष्ठा का उदाहरण माना जा रहा है।

बागी बनें अनुरागी, कृपाशंकर के प्रयासों से बीजेपी में लौटे निर्दलीय प्रत्याशी

भायंदर (उत्तरशक्ति)। भारतीय जनता पार्टी की गढ़ कहे जाने वाले मीरा भायंदर में उत्तर भारतीयों और राजस्थानियों की संख्या करीब 35 से 40 प्रतिशत है। इस बात का ध्यान रखते हुए भाजपा ने 14 उत्तर भारतीयों तथा 14 राजस्थानियों को टिकट दिया। इसके बावजूद कुछ वार्डों में बागी तेवर दिखाई दिए।

प्रभाग क्रमांक 3 में जहां एडवोकेट राजकुमार मिश्रा ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया, वहीं प्रभाग क्रमांक 18 में बीजेपी की प्रदेश पदाधिकारी रेनू मल्लाह ने बागी तेवर दिखाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस बात की जानकारी होते ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री तथा लोकप्रिय उत्तर भारतीय नेता कृपाशंकर सिंह ने सार्थक पहल करते हुए दोनों बागी प्रत्याशियों को नाम वापस लेने के लिए मनाया। दोनों प्रत्याशियों ने कहा कि वे पार्टी नेतृत्व से पूरी तरह से संतुष्ट हैं तथा पार्टी के 70 पार अभियान को सफल बनाने के लिए समर्पित भावना के साथ काम करेंगे।

काव्यसृजन न्यास द्वारा कजरी काव्य संग्रह सावनी फुहार का भव्य लोकार्पण

पालघर(उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। नववर्ष 1 जनवरी 2026 साहित्य प्रेमियों के लिए विशेष उल्लास लेकर आया, जब काव्यसृजन न्यास के तत्वावधान में लोकभाषा कजरी का साझा काव्य संग्रह सावनी फुहार का भव्य लोकार्पण वसई पूर्व स्थित अन्वेषी सदन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय गजलकार डॉ. सागर त्रिपाठी, तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी के सचिव आ. ईश्वर करण, वरिष्ठ साहित्यकार अमित दूबे, उदयनारायण सिंह निर्झर एवं ज्योतिषविद् पं. लक्ष्मीश्वर मिश्र ने अपने करकमलों से पुस्तक का विमोचन किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. सागर त्रिपाठी ने की, जबकि संचालन काव्यसृजन के संस्थापक अध्यक्ष पं. जमदग्निपुरी ने किया। यह बहुप्रतीक्षित कृति हमरूह प्रकाशन और काव्यसृजन न्यास के संयुक्त प्रयास से प्रकाशित हुई है। माँ सरस्वती के पूजन के उपरांत भव्य काव्यगोष्ठी का आयोजन किया गया। आत्मिक श्रीधर मिश्र द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना ने वातावरण को साहित्यिक गरिमा से भर दिया। इसके बाद महानगर व उपनगर के अनेक कवि-कवयित्रियों ने अपनी सशक्त और भावपूर्ण रचनाओं का पाठ किया।

तालियों की गड़गड़ाहट और वाह-वाह से पूरा सभागार गूंज उठा। काव्यपाठ करने वालों में प्रमुख रूप से संदीप प्रजापति, आनंद पाण्डेय केवल, डॉ. प्रमोद पल्लवित, हौसिला प्रसाद अन्वेषी, अरुण दूबे अविकल, हीरालाल यादव हीरा, ताज मोहम्मद सिद्दीकी, अवधेश विश्वकर्मा नमन, सजनलाल यादव, ओमप्रकाश तिवारी, वाचस्पति तिवारी, ओमशरण मिश्र, विनोद कुमार सिंह, मुरलीधर पाण्डेय, अमित दूबे, उदयनारायण सिंह निर्झर, लक्ष्मीश्वर मिश्र, डॉ. सागर त्रिपाठी, ईश्वर करण, पं. जमदग्निपुरी, डॉ. मृदुल तिवारी महक, इंदू मिश्रा, रामजीत गुप्त, आत्मिक श्रीधर मिश्र, दीपक खेर, अमरनाथ दूबे सहित अनेक रचनाकार शामिल रहे। इस अवसर पर भोलानाथ मिश्र, परमानंद राय, अजय राय, उमेश गुप्ता सहित कई गणमान्य साहित्यप्रेमी उपस्थित रहे। अतिथियों का सम्मान अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ से किया गया। राष्ट्रगान के उपरांत संस्था के उप-सचिव आनंद पाण्डेय केवल ने आभार व्यक्त किया। अल्पाहार के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

विवेक उपाध्याय ने लिया लल्लन तिवारी और कृपाशंकर सिंह का आशीर्वाद

भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा भायंदर महानगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिन 14 उत्तर भारतीयों को टिकट दिया है, उसमें से प्रभाग क्रमांक 18 के प्रत्याशी विवेक उपाध्याय सबसे युवा और विनम्र चेहरा माने जा रहे हैं। आज उन्होंने देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान राहुल एजुकेशन के चेयरमैन प्रख्यात समाजसेवी लल्लन तिवारी और उत्तर भारतीयों के सबसे लोकप्रिय नेता तथा महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर विवेक उपाध्याय के चाचा बिल्डर सुरेंद्र उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संतोष दिक्षित, जिला महामंत्री कमलेश दुबे, भाजपा नेता एडवोकेट राजकुमार मिश्रा, जिला महामंत्री बृजेश तिवारी समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। विवेक के दादा स्वर्गीय देवी प्रसाद उपाध्याय दो बार उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे। वर्ष 2013 में बीजेपी विद्यार्थी सेल के वार्ड अध्यक्ष के रूप में राजनीति में पदार्पण करने वाले विवेक उपाध्याय, मंडल युवा उपाध्यक्ष, सोशल मीडिया के जिला संयोजक की जिम्मेदारी का सराहनीय निर्वहन करने के बाद जिला महामंत्री की भूमिका में पार्टी के लिए लगातार समर्पित भावना और संपूर्ण निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। युवाओं में विशेष लोकप्रिय विवेक उपाध्याय का मानना है कि राजनीति सेवा का सबसे प्रभावशाली माध्यम है।

राजनीति में पारदर्शिता और ईमानदारी के पक्षधर रहे विवेक उपाध्याय ने विधायक नरेंद्र मेहता का विशेष आभार मानते हुए कहा कि पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकताओं के साथ-साथ सभी समाज का प्यार और आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना मेरी प्राथमिकता होगी।

शिवसेना बीजेपी युति के सामने विरोधियों का आत्मसमर्पण

कल्याण (उत्तरशक्ति)। कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना-भाजपा महायुति ने इतिहास रचने वाला मास्टरस्ट्रोक खेला है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे की सफल रणनीति के कारण विरोधी पक्ष के कई दिग्गज उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे चुनाव और मतदान से पहले ही महायुति के 20 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं।

गुरुवार को भी दोनों की संयुक्त रणनीति से महायुति के 9 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। आज शुक्रवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था, इसलिए दोपहर 1 बजे से पहले भाजपा और उसके बाद शिवसेना के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाने की जानकारी सामने आई।

इन दोनों के कुल 11 और उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाने से केडीएमसी चुनाव में नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। केडीएमसी के चुनाव इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार कभी भी निर्विरोध नहीं चुने गए थे। महायुति के इन निर्विरोध उम्मीदवारों में कल्याण पूर्व, डोंबिवली पूर्व और डोंबिवली पश्चिम के पैनल शामिल हैं। हालांकि, कल्याण पश्चिम से किसी भी पैनल से निर्विरोध उम्मीदवार नहीं चुना गया है। इस घटना से केडीएमसी में महायुति की स्थिति और मजबूत हुई है और शेष प्रभागों में चुनाव लड़ने के लिए शिवसेना-भाजपा महायुति को बड़ा मनोबल मिला है। वहीं, इतने दिनों से भाजपा और शिवसेना महायुति पर हमला करने वाले शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) और मनसे जैसे प्रमुख विरोधी दलों के उम्मीदवारों ने मैदान छोड़ने की नीति अपनाकर महायुति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।

एमएम यादव को कांग्रेस ने ठुकराया, अजीत पवार ने गले लगाया

मुंबई (उत्तरशक्ति)। पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही बनकर, पार्टी के लिए समर्पित भावना के साथ काम करने वाले एमएम यादव ने जोगेश्वरी पश्चिम स्थित वार्ड क्रमांक 63 से टिकट मांगा। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके समर्पित कार्यों को देखते हुए पार्टी टिकट जरूर देगी। परंतु सियासत के खेल ने उन्हें बाहर कर दिया। कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया, जिसका वार्ड में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार को जब यह बात मालूम पड़ी तो उन्होंने श्री यादव को अपने बंगले पर बुलाकर सम्मान के साथ उन्हें अपनी पार्टी का टिकट दिया। 1985 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे श्री यादव ने सुनील दत्त प्रिया दत्त गुरु दास कामत को चुनाव में जिताने से लेकर बलदेव खोसा को चार बार विधायक बनाने में कड़ी मेहनत की है। महापालिका चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए कड़ी मेहनत की। श्री यादव कांग्रेस पार्टी में अनेक पदों पर रहे। कोरोना संकट काल में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों की भलाई के लिए अनेक काम किए। गुरुदास कामत के अत्यंत करीबी रहे एमएम यादव कांग्रेस के बुरे दिनों में भी चट्टान की तरह खड़े रहे। ऐसे में उनका टिकट काटकर कांग्रेस ने बड़ी भूल की है। उसे चुनाव में इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है।

पालघर में सुरंग ब्रेकथ्रू के साथ बुलेट ट्रेन को मिली नई रफ्तार, पहाड़ काट कर भविष्य की पटरी बिछाई गई

मुंबई। भारत की महत्वाकांक्षी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में पहाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाली सबसे लंबी सुरंग का ब्रेकथ्रू सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि यह इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहली पर्वतीय सुरंग है, जिसे तकनीकी रूप से सबसे कठिन माना जा रहा था। इस उपलब्धि के साथ ही परियोजना को लेकर लंबे समय से उठ रहे सवालों के बीच निर्माण कार्य को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी है।

हम आपको बता दें कि इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग पांच सौ आठ किलोमीटर है, जिस पर बारह स्टेशन प्रस्तावित हैं। यह ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी को लगभग दो घंटे में तय करने में सक्षम होगी। परियोजना में अधिकतर ट्रैक एलिवेटेड वायडक्ट पर बनाया जा रहा है, ताकि रफ्तार और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सकें। सुरंग निर्माण के साथ-साथ पुलों और नदी पार संरचनाओं का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

पालघर की यह सुरंग खास इसलिए भी है क्योंकि इसका निर्माण जटिल भूगर्भीय परिस्थितियों में किया गया है। चट्टानी जमीन, पानी का दबाव और पर्यावरणीय चुनौतियों के बावजूद इंजीनियरों और मजदूरों ने इस चरण को पूरा कर दिखाया। रेल मंत्रालय का कहना है कि यह सफलता आने वाले समय में अन्य सुरंगों और कठिन हिस्सों के निर्माण का रास्ता आसान बनाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बुलेट ट्रेन केवल आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विकास को गति देने वाली परियोजना है।

देखा जाये तो पालघर की सुरंग का ब्रेकथ्रू केवल इंजीनियरिंग की जीत नहीं है, यह उस मानसिकता पर भी करारा प्रहार है जो हर बड़े भारतीय प्रोजेक्ट को पहले दिन से असफल घोषित कर देती है। वर्षों तक कहा गया कि यह परियोजना बहुत महंगी है, बहुत कठिन है और भारत इसके लायक नहीं है। आज वही पहाड़ चुप हैं और आलोचक बगले झांक रहे हैं।

यह सवाल उठाना जायज है कि इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, लेकिन यह पूछना भी उतना ही जरूरी है कि क्या भारत हमेशा छोटे सपनों तक सीमित रहेगा। जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हाई स्पीड रेल को विकास का औजार बना चुकी हैं, तो भारत को इससे वंचित रखने की जिद आखिर किसके हित में है। बुलेट ट्रेन आराम या शान का प्रतीक नहीं, बल्कि समय की बचत, उत्पादकता की बढ़ोतरी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद है।

यह सुरंग इस बात का सबूत है कि अगर नीति स्पष्ट हो और इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो भारत किसी भी तकनीकी चुनौती को पार कर सकता है। बार बार अड़ंगे, मुकदमे और शोर शराबे के बावजूद काम आगे बढ़ा है। यही वह बात है जो इस परियोजना को खास बनाती है। विकास कभी शोर में नहीं, बल्कि काम में दिखाई देता है।

अब सरकार के सामने असली परीक्षा है। परियोजना समय पर पूरी हो, लागत नियंत्रण में रहे और इसके फायदे आम आदमी तक पहुंचें। यदि ऐसा हुआ, तो पालघर की यह सुरंग सिर्फ पहाड़ के आर पार का रास्ता नहीं होगी।

उत्तरशक्ति

* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।

पत्राचार कार्यालय:
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामीः शरद फागूराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * **संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति,** समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, **मो.-** 9554493941 **email ID- uttarshaktinews@gmail.com**

जांच करने पहुँची महिलाकर्मी को धमकी देने, बदतमीजी करने पर ब्लाक कर्मी विफरे, दी तहरीर

मामला सिकरारा थाना के भुआखुर्द का, दो के विरुद्ध मुकदमा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सिकरारा थाना क्षेत्र के भुआखुर्द गांव में बुधवार को एक शिकायत कर्ता के शिकायत की जांच करने गई तीन सदस्यीय टीम के साथ शिकायत कर्ता द्वारा ही महिला कर्मी व टीम को एससी एसटी में फसाने की धमकी देने के साथ ही अन्य लोगो से बदतमीजी करते हुए सरकारी फाइल व कागजात फाड़ने का मामला प्रकाश में आया है।मनबढ़ों की इस करतूत से ब्लाककर्मी विफर गए, नववर्ष की सुबह ही ब्लाक के सहयोगियों के साथ थाने पहुँचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।पुलिस मिली तहरीर के आधार पर सरकारी काम मे बाधा,महिला कर्मी से बदसलूकी से सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई।

क्षेत्र के भुआखुर्द गांव में तैनात महिला सचिव सारिका मौर्य गुरुवार सुबह एडीओ सहकारिता ब्रह्मजीत सिंह, सहयोगी सचिव प्रदीपशंकर श्रीवास्तव, राजकुमार पाण्डेय, वीरेंद्र सरोज, अखिलेश सरोज सहित दर्जभर ब्लाक सहयोगियों के साथ थाने पहुँचकर तहरीर दी कि बुधवार को खण्ड विकास अधिकारी पवन कुमार प्रजापति के निर्देश पर गांव के शिकायत कर्ता अग्निकेतु पुत्र स्व जियालाल की शिकायत पर गठित तीन सदस्यीय टीम जिसमे एडीओ एजी सकलनारायण पटेल, जेई आर ई डी सत्यम सिंह व तकनीकी सहायक मनीष चंद के साथ गांव के रामनारायण पुत्र रामनिहोर के आवास की जांच कर रहे थे तभी शिकायत कर्ता अग्निकेतु, मुंशीराम पुत्र बरखू व अन्य लोग आकर मुझे लक्ष्य करके भद्दी भद्दी गाली देते हुए एससी एसटी में फसाने की धमकी देते हुए टीम के कर्मियों के साथ बदसलूकी करते हुए सरकारी कागजात व फाइल छीनकर फाड़कर फेक दिए। थानाध्यक्ष उदयप्रताप सिंह तहरीर लेकर दो के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गए।

राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव की पहल पर नए वर्ष में जनपद जौनपुर को मिली बड़ी सौगात

गुरैनी, मानीकलां, सोंगर, मार्टिनगंज मार्ग के लिए 28 करोड़, 28 लाख का भारी भरकम बजट स्वीकृत

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग गिरीश चंद्र यादव की पहल पर जौनपुर जिले को नए वर्ष 2026 में एक बड़ी सौगात मिली है। शाहगंज विकासखंड के गुरैनी, मानीकलां, सोंगर, होकर मार्टिनगंज तक जाने वाली इस बहुप्रतिक्षित सड़क मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 28 करोड़ 28.40 लाख की भारी भरकम धनराशि प्रदेश शासन से स्वीकृत कराया है।

जनपद जौनपुर और आजमगढ़ होकर सीधे गोरखपुर को जोड़ने वाली यह सड़क मार्ग 14.800 यानी करीब 15 किलोमीटर चौड़ी होगी। जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के शाहगंज विकासखंड अंतर्गत खेतासराय, खुटहन, गुरैनी, मानीकला के हजारों लोगों को अब आजमगढ़ मंडल मुख्यालय पर आने जाने के लिए शानदार बढ़िया चौड़ी सड़क मिलेगी। इससे जहां आवागमन के बेहतर साधन होंगे। वहीं इलाके के लोगों को रोजगार कारोबार के सिलसिले में यह सड़क काफी मुफीद साबित होगी। गुरैनी, मानीकलां, सोंगर, होकर मार्टिनगंज तक जाने वाली बहु प्रतिक्षित सड़क मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 28 करोड़ 28.40 लाख की भारी भरकम धनराशि प्रदेश शासन से स्वीकृत कराया है।

करीब साढे 28 करोड़ के इस भारी भरकम बजट से दो जिलों को जोड़ने वाली यह सड़क

14.800 यानी करीब 15 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के सुदृढ़ होने की खबर से पूरे क्षेत्र में खुशियों की बहार आ गई है।

जौनपुर सदर विधानसभा के विधायक और प्रदेश सरकार के लोकप्रिय राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव से इस सड़क के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के लिए पिछले काफी लंबे समय से क्षेत्रीय जनता मांग कर रही थी। क्योंकि पूर्व की सरकारों के शासनकाल में यह सड़क निरंतर उपेक्षित पड़ी हुई थी।

क्षेत्रीय जनता के निरंतर मांग पर राज्यमंत्री यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपने विधानसभा क्षेत्र की कई सड़कों के विकास का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा। जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत मामले की गंभीरता को

जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर का क्षेत्रीय सड़कों से होगा सीधे जुड़ाव

लेते हुए धन आवंटित करवा दिया। इस संबंध में प्रदेश के खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव के मीडिया प्रतिनिधि मनीष श्रीवास्तव ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज में बताया कि आजादी के बाद से अभी तक यह सड़क उपेक्षित पड़ी थी।

राज्यमंत्री की पहल पर जनता को मिलेगा लाभ - प्रदेश के खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव की इस शानदार पहल पर ग्रामीण अंचल में रहने वाले किसानों, नौजवानों को नए रोजगार के आयाम मिलेंगे। राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि हमारी सरकार ने इसके लिए करीब 28 करोड़, 28 लाख का भारी भरकम बजट स्वीकृत कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे जौनपुर, आजमगढ़ दो जिलों को जोड़ने का बेहतर मार्ग प्रशस्त होगा। इलाके के किसानों को अपने-अपने साग सब्जी, अनाज फल फ्रूट व अन्य कारोबार गोरखपुर,आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के अन्य मंडियों में लाने ले जाने और बिक्री करने में मदद मिलेगी।

जनपद जौनपुर में लुम्बिनी-दुद्धी राष्ट्रीय राज मार्ग से जुड़ी सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु रु0 9.26 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रदेश के खेल व युवा कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया है।

राज्यमंत्री यादव ने बताया कि जौनपुर-लुम्बिनी दुद्धी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-135) के किमी 234 से इंदिरा गांधी स्टेडियम एवं केंद्रीय विद्यालय होते हुए करंजाकला तक संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को गति देगी। इससे जौनपुर जनपद के आसपास स्थित एक्सप्रेस वे और भावी रिंग रोड से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सशक्त होगी और आमजन को सुगम एवं सुरक्षित यातायात सुविधा प्राप्त होगी।

26 जनवरी को लाल किले के तिरंगे को सलामी देंगे बदलापुर के स्वयंसेवी

बदलापुर,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सल्तनत बहादुर महाविद्यालय बदलापुर जौनपुर से राष्ट्रीय सेवा योजना के 2 स्वयंसेवियों अनीशा पाण्डेय तथा गौरव जायसवाल का चयन गणतंत्र दिवस पर होने वाले परेड के लिए किया गया है। इस चयन से महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो0 सुनील प्रताप सिंह, प्रबंधक श्याम सिंह, कार्यक्रम अधिकारियों एवं महाविद्यालय के प्राध्यापको, कर्मचारियों ने खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयक डॉ0 राजबहादुर यादव ने भी स्वयंसेवियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए प्रसन्नता

जाहिर की। चयनित स्वयं सेवकों को एक माह के लिए दिल्ली में भारत सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसमें संपूर्ण भारत से 200 स्वयंसेवक एवं सेविकाएं प्रतिभाग करेंगे और 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर सलामी देंगे। इनका चयन महाविद्यालय स्तर, विश्वविद्यालय स्तर तथा प्रदेश स्तर से होते हुए किया गया है। इस 30 दिवसीय शिविर में ये सभी स्वयंसेवी भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत पर अपने विचारों को भी साझा करेंगे इनके चयन पर कार्यक्रम अधिकारी डॉ0 एम0 ए0 अंसारी ने इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना प्रेषित की।

मिशन शक्ति के तहत केराकत में महिलाओं-बालिकाओं को किया गया जागरूक

एंटी रोमियो टीम ने बाजारों में चलाया सुरक्षा जागरूकता अभियान

केराकत, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। नववर्ष के दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह केराकत कोतवाली पुलिस ने

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। यह अभियान मिशन शक्ति फेज5 के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम प्रभारी उपनिरीक्षक बबन सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया।

अभियान के दौरान पुलिस टीम ने कोतवाली चौराहा, सरायबीरू, सिहौली चौराहा, स्टेशन रोड सहित अन्य प्रमुख बाजारों में सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। पुलिस ने उन्हें किसी भी आपात स्थिति में बिना संकोच पुलिस से संपर्क करने और उपलब्ध हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर महिलाओं को पुलिस आपात सेवा 112, एंबुलेंस सेवा 102 व 108, वूमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 तथा साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 की जानकारी दी गई। साथ ही विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, नशा मुक्ति भारत अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों के बारे में भी बताया गया।

उपनिरीक्षक बबन सिंह ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न या अपराध की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

अभियान में हेड कांस्टेबल संजय यादव, महिला कांस्टेबल कुसुम, आशा, अनुपमा, होमगार्ड जवान रामविलास यादव, रविंद्र सहित अन्य पुलिसकर्मी व स्थानीय लोग मौजूद रहे।

मृत्युंजय महादेव धाम उमरछा में गूंजा सुंदरकांड, भक्ति-संगीत से भावविभोर हुए श्रद्धालु

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। मृत्युंजय महादेव धाम उमरछा में प्रत्येक माह प्रदोष व्रत के अवसर पर आयोजित होने वाली सस्वर सुंदरकांड पाठ प्रतियोगिता इस बार भी भव्यता और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुई। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के पंचम कांड सुंदरकांड की संगीतमय प्रस्तुति ने पूरे परिसर को भक्तिरस से सराबोर कर दिया।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जौनपुर सुशील कुमार उपाध्याय ने कहा कि सुंदरकांड केवल एक धार्मिक पाठ नहीं, बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने का सफलता सूत्र है। इसमें भक्त हनुमान के पराक्रम, बुद्धि और अटूट विश्वास का अद्भुत वर्णन मिलता है, जो हर व्यक्ति को संकल्प और समर्पण की प्रेरणा देता है। उन्होंने श्वेता प्रियांशी रामचरित मानस समिति, मलिकानपुर के कलाकारों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मधुर और भावपूर्ण प्रस्तुति ने लंका दहन और राम-हनुमान मिलन की जीवंत अनुभूति करा दी।

कार्यक्रम की शुरुआत पंडित हीरामणी उपाध्याय के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यजमान शेषनाथ शुक्ल एवं उनकी धर्मपत्नी द्वारा विधिवत पूजन से हुई। निर्णायक मंडल में ललित शुक्ल, कैलाशनाथ शुक्ल और सतीश कुमार उपाध्याय शामिल रहे, जिन्होंने निर्णय को बंद लिफाफे में सुरक्षित रखा।

जिला मीडिया प्रभारी आमोद सिंह ने सुंदरकांड के आध्यात्मिक और मानसिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए इसे अत्यंत शुभ और शक्तिशाली बताया। कार्यक्रम में अतिथियों, प्रतिभागियों और सहयोगियों का स्मृति चिह्न व अंगवस्त्र देकर सम्मान किया गया। अंत में आरती के पश्चात भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों महिला-पुरुष श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

राहुल मिश्रा आत्महत्या मामले में धरना स्थगित

डीसीपी वरुणा से वार्ता के बाद फैसला, मुख्य आरोपी शुभम अभी फरार

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद के लोहता थाना क्षेत्र के बनकट गांव में राहुल मिश्रा की आत्महत्या के मामले में परिवार की ओर से न्याय की मांग को लेकर प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरना स्थगित कर दिया गया है। मृतक की मां की ओर से आज सुबह 12 बजे शास्त्री घाट पर धरने पर बैठने की

घोषणा की गई थी,लेकिन डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार के फोन आने और वार्ता के लिए बुलाने पर यह धरना टाल दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सीमा चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी उन्होंने लिखा कि वाराणसी बनकट में राहुल मिश्रा की मौत के बाद पुलिस ने उसकी सास और पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है,लेकिन मुख्य अभियुक्त शुभम उर्फ डेंजर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है मृतक की मां के आंसुओं को देखकर पुलिस से बात की गई,लेकिन कोई विकल्प न निकलने देख धरने की तैयारी थी। सीमा चौधरी ने आगे बताया कि उनके घर पर इस समय लोहता थाना प्रभारी मौजूद हैं डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार से वार्ता के बाद धरने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा तब तक के लिए धरना स्थगित माना जाए,उन्होंने दोहराया कि हमारी मांग अभी भी यही है कि सभी दोषियों को जेल भेजा जाए,ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। गौरतलब है कि राहुल मिश्रा ने दिसंबर 2025 में आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया था,जिसमें पत्नी संध्या,सास और शुभम सिंह उर्फ डेंजर पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने पत्नी और सास को गिरफ्तार किया है,जबकि शुभम की तलाश जारी है।परिवार लगातार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और न्याय की मांग कर रहा है।

प्रशासनिक किले में सेंध!

तहसील शाहगंज से अधिवक्ता का मोबाइल चोरी, खाते से उड़े 87 हजार

विशाल सोनी

शाहगंज,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। प्रशासनिक सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खोलती हुई तहसील शाहगंज परिसर से चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। अधिवक्ताओं और फरियादियों से भरे रहने वाले इस परिसर में अज्ञात शातिरों ने एक अधिवक्ता का मोबाइल फोन चुरा लिया और उसी के जरिए बैंक खाते से 87 हजार रुपये निकाल लिए। घटना के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया।

ग्राम रामपुर निवासी एवं तहसील शाहगंज में विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंह का मोबाइल फोन 18 दिसंबर 2025 को तहसील परिसर से चोरी हुआ। चोरी के कुछ ही समय बाद शातिरों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा बड़गांव, शाहगंज में संचालित खाते से 87,000 रुपये की अवैध निकासी कर ली।

पीड़ित ने तत्काल कोतवाली शाहगंज और संबंधित अधिकारियों को लिखित सूचना दी, लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद न मोबाइल की बरामदगी हो सकी है और न ही खाते से निकाली गई रकम का कोई सुराग मिला है।

घटना ने तहसील परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अधिवक्ताओं और आम नागरिकों का कहना है कि यदि प्रशासनिक परिसर ही सुरक्षित नहीं है, तो आमजन की सुरक्षा की गारंटी कैसे दी जा सकती है। पीड़ित अधिवक्ता ने क्षेत्राधिकारी शाहगंज से पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।

बबरखा ग्राम पंचायत में उचित दर दुकान आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उपजिलाधिकारी सदर ने बताया कि तहसील सदर के विकास खंड करंजाकला अंतर्गत ग्राम पंचायत बबरखा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित होने वाली उचित दर दुकान वर्तमान में रिक्त है। उक्त दुकान के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह दुकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए वर्टिकल आरक्षण के अंतर्गत निर्धारित है।

उपजिलाधिकारी ने बताया कि आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल या समकक्ष होनी चाहिए तथा आयु 21 वर्ष से अधिक हो। अभ्यर्थी के बैंक खाते में कम से कम 40 हजार रुपये उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिससे वह एक माह का खाद्यान्न एक साथ उठा सके। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक स्थानीय निवासी हो और परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई अन्य उचित दर दुकान आवंटित न हो।

आवेदन के साथ जिला पूर्ति अधिकारी के पक्ष में एक हजार रुपये की अर्नेस्ट मनी बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। दुकान आवंटन की स्थिति में 10 हजार रुपये की प्रतिभूति राशि तथा 100 रुपये का नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप देना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी या उसके परिवार के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो तथा पूर्व में अनियमितता के कारण दुकान निरस्त न हुई हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राम प्रधान अथवा उनके परिवार के सदस्यों के पक्ष में दुकान का आवंटन नहीं किया जाएगा।

इच्छुक अभ्यर्थी 1 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक किसी भी कार्यदिवस में तहसील सदर स्थित आपूर्ति कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर 15 जनवरी 2026 की सायं 5 बजे तक पूर्ण अभिलेखों सहित जमा कर सकते हैं। आवेदनों की जांच 16 जनवरी को की जाएगी तथा पात्र अभ्यर्थियों के मध्य 17 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे तहसील सदर कार्यालय में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।

रंगमंच की गंगा कितनी पावन कितनी पतित विषयक गोष्ठी सपन्न

प्रयागराज (उत्तरशक्ति)। अभिनव सांस्कृतिक संगठन के तत्वावधान में अपने 49वें स्थापना दिवस पर कार्यालय कालाडांडा प्रयागराज में रंगमंच की गंगा कितनी पावन, कितनी पतित विषय पर एक विचारोत्तेजक गोष्ठी का आयोजन सम्पन्न हुआ। गोष्ठी में रंगमंच की वर्तमान स्थिति, उसकी वैचारिक शुचिता, सामाजिक दायित्व और समकालीन चुनौतियों पर गंभीर विमर्श किया गया।

गोष्ठी में प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रीय चित्रकार रवीन्द्र कुशवाहा ने रंगमंच की तुलना गंगा के प्रवाह से करते हुए कहा कि इसमें पवित्रता अत्यधिक और विकृतियाँ कम हैं थोड़ी सावधानी बरती जाए तो विकृतियाँ खत्म हो सकती हैं। वरिष्ठ निर्देशक अजय मुखर्जी ने रंगमंच की सामाजिक प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि रंगकर्म तभी सार्थक है जब वह जनसरोकारों से जुड़ा रहे। वरिष्ठ रंगकर्मी सुबोध सिंह, गुरविंदर सिंह तथा राकेश वर्मा ने समकालीन रंगमंच में व्यावसायिक दबाव, मौलिकता के संकट और दर्शक-संवेदना पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने चिंता व्यक्त की कि आज रंगमंच को अपनी पावन परंपरा और वैचारिक गरिमा को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा है।

कार्यक्रम में ऋचा शुक्ला, समृद्धि गौड़, शादमा खातून, अभिषेक सिंह रेडियो कम्पेयर एवं रंगकर्मी तथा प्रमिल अस्थाना अभिनव के प्रथम सचिव, अजय मुखर्जी विनोद रस्तोगी संस्थान से, आलोक नगर द थर्ड बेल संस्था से, राकेश वर्मा समवांतर संस्था से, अभिनव संस्था की वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रतिमा श्रीवास्तव तथा संस्थापक सचिव प्रवीण अस्थाना सहित प्रयागराज के अनेक महत्वपूर्ण और सक्रिय रंगकर्मियों की उल्लेखनीय व्याख्यान रहे। गोष्ठी के दौरान खुली चर्चा में युवा कलाकारों ने भी सक्रिय सहभागिता की। गोष्ठी का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि रंगमंच की गंगा को वैचारिक रूप से निर्मल, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और सृजनात्मक रूप से जीवंत बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे।

शहर की धड़कन पर कीचड़ का कब्जा

डॉ.इम्तियाज अहमद

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। शहर के हृदय स्थल "चहारसू चौराहे से सद्भावना पुल की ओर जाने वाला मार्ग आज बदहाली का जीता-जागता उदाहरण बन चुका है।

यह वही सड़क है जहाँ दिनभर हजारों लोग, छोटे व्यापारी, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग आवाजाही करते हैं। सड़क के दोनों किनारों पर खाने-पीने की दुकानें हैं, ट्रैफिक का दबाव है, लेकिन रोड के बीचों-बीच भरा कीचड़ और गंदा पानी। कभी भी किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है।

बारिश हो या न हो, सड़क पर जमा कीचड़ और फिसलन भरा पानी आए दिन एक्सीडेंट का कारण बन

चहारसू-सद्भावना पुल मार्ग बना जनसंकट

रहा है। दोपहिया वाहन फिसल रहे हैं, पैदल चलना मुश्किल हो गया है, और दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इसी रास्ते से जनपद के तमाम नेता और अधिकारी रोजाना गुजरते हैं तो फिर महीनों से इस बदहाल सड़क पर किसी जिम्मेदार

की नजर क्यों नहीं पड़ रही। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है, क्या आम जनता की परेशानी अब व्यवस्था के लिए मायने नहीं रखती।

यह सड़क कोई गली-मोहल्ले की नहीं, बल्कि शहर की चुनिंदा अतिव्यस्त सड़कों में से एक है। इसके बावजूद न मरम्मत, न जलनिकासी, न ही कोई स्थायी समाधान। संबंधित विभागों से मांग है कि इस सड़क की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जलनिकासी, सड़क की मरम्मत और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था। जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ सड़क नहीं, लोगों की जान का मामला है।

नौपेडवा बाजार में रोडवेज बसों की अन्दर जाने की मांग

-मोहम्मद जावेद

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। नौपेडवा बाजार के दीपक निगम (पिंटू) निवासी गल्ला मंडी ने कहा रोडवेज की बसें नौपेडवा बाजार से न होकर हाईवे से निकलती हैं। जबकि यात्री बाजार में अधिक हैं। मार्केट में बसे ना जाने से लोग यातायात से प्रभावित हो रहे हैं। जिससे महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग आदि लोग नौपेडवा हाईवे दिन हो या रात को उतरते हैं, तो सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं दीपक निगम का कहना है। शराब का ठेका भी बगल में है हाईवे के पास, जिससे लोगों में भय बना रहता है। उन्होंने कहा कई बार अधिकारियों को सूचित किया गया है पर सुनवाई नहीं हुई और ना ही कोई गंभीरता से अधिकारी इस बात को ले रहे वही देवराज पांडे ने कहा बसें नौपेडवा से न जाने से मां, बहने, बच्चे और सभी औरतों को यातायात को लेकर असुविधा है उन्होंने अधिकारी से मांग की रोडवेज बसों को मार्केट से ले जाए। दीपक निगम और देवराज पांडे के इस धरने पर मेंहदी, अख्तर मुन्ना कई लोग उपस्थित रहे। मार्केट के सभी लोग जिसमे तेज बहादुर यादव, राजेश कुमार ,विशाल जायसवाल, विजय कुमार ,आशीष जायसवाल, आकाश जायसवाल, राजेश विश्वकर्मा, अभिषेक कुमार, सोनू निगम ,अशोक जायसवाल, मोहम्मद असलम मोहम्मद अख्तर सहित लोगों ने दीपक निगम पिंटू और देवराज के समर्थन में रहे।

चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, चोरी गया सामान बरामद

मीरा भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा रोड में गत 30 दिसंबर 2025 को सुबह, शिकायतकर्ता श्रद्धा अनिल शेलार, जो पेशे से गृहिणी हैं और रसाई निवास पूनम संरगम के बाजु में ग्लोबल फास्टेप स्कूल हाटकेश काशीमीरा मीरा रोड ईस्ट में रहती हैं। अपने पति अनिल शेलार के साथ वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल करने रामदेव पार्क, मीरा रोड गई थीं। दोपहर करीब 13:30 बजे जब वे घर लौटीं, तो उन्होंने पाया कि उनके घर का दरवाजा टूटा हुआ है और घरेलू सामान बिखरा पड़ा है। उस समय, जब उन्होंने लोहे की अलमारी की जाँच की, तो पाया कि अलमारी में तिजोरी में रखी उनकी अपनी सोने की चेन, कंगन, झुमके, गहने, नथनी, गले का हार, कुल 2,16,000 रुपये का सामान, 43 ग्राम सोने के गहने और 20,000 रुपये नकद आदि गायब थे। उन्हें पूरा यकीन था कि जब वे घर पर नहीं थीं, तब किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर का दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया और उक्त सामान चुरा लिया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर, काशीमीरा पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 305, 331(3) के तहत चोरी का मामला दर्ज किया गया है। उक्त अपराध की कुशल जांच के बाद, आरोपियों को भायंदर रेलवे स्टेशन से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे दूसरे राज्य भाग रहे थे।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम इरफान यूसुफ खान, उम्र 25 वर्ष, बेरोजगार, निवासी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, स्टोर बैंक के सामने, साई चाचा नगर, नयानगर, मीरा रोड तालुका ठाणे, सागर दिलीप सोनी, उम्र 23 वर्ष, बेरोजगार, निवासी काली मंदिर जायल, शिवर गार्डन, मीरा रोड तालुका ठाणे, मूल पता गांव धांगड़ी, टिकापुर, पुराना बस्ती जपाल, नेपाल, अजय विजय तोर्ने, उम्र 11 वर्ष, बेरोजगार, निवासी एस.के. स्टोन झुग्गी बस्ती के पास, पुलिस चौकी के नजदीक, कनकिया, मीरा रोड तालुका ठाणे। उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शिकायतकर्ता के चोरी हुए सोने के आभूषण जैसे कंगन, हार, नथ, झुमके, पेंडाल, नकदी और चोरी के अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार उनसे जब्त कर लिया गया है।

गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि नयानगर, नवघर और मीरा रोड पुलिस स्टेशनों में आरोपी संख्या 01 और 02 के खिलाफ चोरी और सेंधमारी के मामले दर्ज हैं, और गिरफ्तार आरोपी को दर्ज मामलों में सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया है।

उपरोक्त कार्य मा, निकेत कौशिक, पुलिस आयुक्त, मीरा भायंदर, वसई विरार, पुलिस आयुक्तालय, मा, दत्तात्रेय शिंदे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, मा, चव्हाण, पुलिस उपायुक्त, जोन 01, मा,. मीरा रोड डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त गणपत पिंगले, कटिंचय पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राहुल कुमार पाटिल के मार्गदर्शन में, संजय पुजारी, पुलिस निरीक्षक (अपराध) अभिजीत लांडे, विजय साठे, आनंद गराडे, पुलिस उप-निरीक्षक, अपराध जांच शाखा, साथ ही अपराध जांच शाखा के अनमलदार पो. हवा प्रताप पांडुडे, पीओए किरण विरकर, नामदेव देवकाते, प्रवीण तोबरे, विक्रांत खंडारे, उमंग चौधरी, अभिषेक महाची, रवींद्र सोनावणे। द्वारा किया गया।

एनएच व बाईपास निर्माण की प्रगति को लेकर डीएम की सख्ती, लंबित मुआवजा तत्काल देने के निर्देश

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) एवं बाईपास निर्माण से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन किसानों को भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष मुआवजा राशि का भुगतान अभी अवशेष है अथवा जिन प्रकरणों में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उनका त्वरित गति से निस्तारण करते हुए शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप एनएच और बाईपास निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराना प्राथमिकता है। डीएम ने दो टूक कहा कि मुआवजा वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि इस कार्य में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, उप जिलाधिकारी केराकत, उप जिलाधिकारी मड़ियाहूं सहित संबंधित तहसीलों के तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं लेखपाल उपस्थित रहे।

उत्तर भारतीय विकास सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश पांडे ने रचा इतिहास

-लाल शेखर सिंह

पालघर (उत्तरशक्ति)। वसई-विरार महानगर पालिका के अंर्तगत उत्तर भारतीयों के हितार्थ काम करने वाली उत्तर भारतीय विकास संस्था जो बहुजन विकास आघाडी द्वारा पुरस्कृत है।उत्तर भारतीय विकास संस्था के संस्थापक अध्यक्ष राजेश पाण्डे क्षेत्र में उत्तर भारतीयो की समस्याओं को सुलझाने में दिन रात लगें रहते हैं। उत्तर भारतीय समाज की परम हितैषी उत्तर भारतीय विकास संस्था के मजबूत स्तंभों में शुमार के. डी. शर्मा, शैलेश तिवारी और अजय सिंह ठाकुर जैसे पुराने भरोसेमंद कार्यकताओं के साथ समाज के सुखदुःख में निरंतर लगे रहते हैं। उत्तर भारतीय विकास संस्था के इन निष्ठा वंत कार्यकताओं पर संस्था के अध्यक्ष राजेश पांडे पूर्ण रूप से विश्वास रखते हुए इनको अपने साथ लेकर समाजसेवा के पुनीत काम में लगे रहते हैं। महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दिया है। इसी क्रम में उत्तर भारतीय समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारतीय विकास संस्था के संस्थापक अध्यक्ष राजेश पाण्डे ने वसई-विरार महानगर पालिका चुनाव में इस बार बहुजन विकास आघाडी पार्टी से क्षेत्र के 10 वार्डो में उत्तर भारतीय प्रत्याशियों को टिकट दिलाकर इतिहास ही रच दिया क्योंकि चुनाव में एक ओर जहाँ अन्य राजनीतिक दलों द्वारा टिकट बँटवारे में उत्तर भारतीय समाज की अनदेखी और उपेक्षा की गयी वहीं बहुजन विकास आघाडी का उत्तर भारतीय समाज के प्रति जताया गया विश्वास प्रसंशनीय एवं स्वागत योग्य है। गौरतलब है कि उत्तरप्रदेश वाराणसी के सीमावर्ती जनपद चंदौली, से आकर वसई-विरार क्षेत्र में उत्तर भारतीय विकास संस्था की स्थापना वास्तव में उत्तर भारतीय समाज के लिए वरदान साबित हुआ। आज मनपा चुनाव में दस उत्तर भारतीयों को बहुजन विकास आघाडी का प्रत्याशी होना उत्तर भारतीय सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश पांडे ही नही, बल्कि पूरे समाज के लिए गौरव की बात है।

नीलगाय और आवारा पशुओं की आतंक से किसान परेशान

सिवान (उत्तरशक्ति)। महाराजगंज बिहार के सीवान जिला के महाराजगंज अनुमंडल क्षेत्र में आजकल नीलगायों और आवारा पशु किसानों के खेतों के फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों को अपनी फसलें बचाने के लिए रातभर खेतों की रखवाली करनी पड़ती है, जो उनकी सेहत और आर्थिक स्थिति दोनों के लिए हानिकारक है कुछ क्षेत्रों में किसानों ने अपनी फसलें बचाने के लिए मचान बनाकर पहरा देना शुरू कर दिया है, लेकिन यह समाधान पर्याप्त नहीं है। सरकार और प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है ।रबी, धनिया, बैगन, सरसों बाकला, लौकी आदि पशुओं के पसंदीदा चारा है जिससे वे आराम से खेतों में चरते हैं।

नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में विशाल प्रजापति ने मारी बाजी

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। उड़ीसा ताइक्वांडो यूनियन के तत्वावधान में आयोजित आठवीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन 31 दिसंबर 2025 को राउलकेला, उड़ीसा में किया गया। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर अंतर्गत ग्राम सभा हमजापुर, बशरतपुर निवासी विशाल प्रजापति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। विशाल प्रजापति, एडवोकेट सुधाकर प्रजापति के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और अनुशासन के बल पर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर आयोजन समिति द्वारा विशाल प्रजापति को विजेता घोषित करते हुए प्रशस्ति पत्र, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि से विशाल प्रजापति ने न केवल अपने परिवार और समाज का, बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। परिजनों, शुभचिंतकों और खेल प्रेमियों ने विशाल को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

आर .जे. शंकरा आई हॉस्पिटल व शोभा एजुकेशनल ट्रस्ट के सहयोग से कमरुद्दीनपुर में नि :शुल्क नेत्र शिविर

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। कमरुद्दीनपुर स्थित सर्वेश्वरी महाविद्यालय परिसर में आर. जे. शंकरा आई हॉस्पिटल, वाराणसी एवं शोभा एजुकेशनल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद चयन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक चला। शिविर का निरीक्षण सुरेरी प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा ने किया। इस दौरान थाना सुरेरी की पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही। थाना प्रभारी राजेश मिश्रा ने शिविर की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। उन्होंने कंबल वितरण में सहभागिता की तथा लोगों से ठंड से बचाव एवं स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की अपील की। इस अवसर पर सर्वेश्वरी महाविद्यालय के प्रबंधक डॉ. परमेंद्र कुमार सिंह द्वारा थाना प्रभारी राजेश मिश्रा को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। शिविर में मरीजों की शुगर, ब्लड प्रेशर एवं आंखों की जांच की गई। जांच के उपरांत मोतियाबिंद से पीड़ित लगभग 60 मरीजों को ऑपरेशन हेतु चयनित किया गया। चयनित मरीजों को निःशुल्क बस द्वारा आर. जे. शंकरा आई हॉस्पिटल, वाराणसी भेजा जाएगा, जहां उनका इलाज, ऑपरेशन एवं भोजन की व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। कार्यक्रम के दौरान डॉ. परमेंद्र कुमार सिंह ने अपनी माता स्वर्गीय शोभा सिंह की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर लगभग 100 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही इस अवसर पर सोनाली सिंह एवं रोशनी बानो को टैबलेट वितरित किए गए। शिविर को सफल बनाने में आर. जे. शंकरा आई हॉस्पिटल की मेडिकल टीम–डॉ. गणेश, अनुराधा, डॉ. अंशिका, डॉ. प्रतिभा एवं डॉ. हरिशंकर–के साथ डॉ. संजय सिंह, अशोक पटेल, डॉ. मंजू सिंह, डॉ. आभा तिवारी, विभा तिवारी, अलका यादव, डॉ. वंदना सिंह, मंजू पांडे, ज्ञान प्रकाश पांडे, सत्येंद्र सिंह, अनिल सिंह, दिलीप कुमार सिंह, सर्वेश यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

न्यायमूर्ति वाणी रंजन अग्रवाल का आगमन 3 जनवरी को

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। प्रयागराज उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल का आगमन 3 जनवरी को जौनपुर हो रहा हैं। प्राप्त प्रोटोकॉल के अनुसार प्रातः 10 बजे प्रयागराज से प्रस्थान कर 12 बजे जौनपुर डाक बंगला लाइन बाजार न्यायमूर्ति आएंगी। दोपहर 1 बजे दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ जौनपुर द्वारा आयोजित स्व संतोष कुमार श्रीवास्तव संतोषी बाबू वरिष्ठ अधिवक्ता के पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा एवं एक सेमिनार त्वरित न्याय प्रक्रिया में न्याय पालिका कार्य पालिका विधायकी की भूमिका पर आयोजित सेमिनार में भाग लेंगी एवं अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित अन्य उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगी। उक्त सेमिनार में जिला जज सुशील कुमार शशि, जिलाधिकारी दिनेश चन्द सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. कौशतुभ सहित बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य एवं जौनपुर के अधिवक्ता बंधु भाग लेने। दोपहर 3 बजे न्यायमूर्ति माता शीतला चौकियां मंदिर में दर्शन पूजन करने के उपरान्त प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगी। उक्त आशय की जानकारी देते हुए अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव, मंत्री रण बहादुर यादव ने देते हुए अधिवक्ता बंधुओं से भाग लेने का अनुरोध किया।

विधायक राजन नाईक की उपस्थिति में कई युवाओं ने थामा भाजपा का दामन

नालासोपारा। नालासोपारा युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी एवं वार्ड क्रमांक 15 से भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार विजय तिवारी के नेतृत्व में आज कई युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक रूप से प्रवेश किया। यह पार्टी प्रवेश विधायक राजन नाईक की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। भाजपा में शामिल होने वालों में निखार जाधव, प्रग्नेश ठक्कर, प्रेम चौहान, हेरात जाधव, योगेश येरेवा, सूरज पाटडे, संतोष परब, समीर शेख, राजिश वडुदेवन और रवि गुप्ता अपने साथियों सहित शामिल हैं। सभी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में विश्वास जताते हुए और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रहितैषी विचारधारा से प्रेरित होकर पार्टी में प्रवेश किया। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं ने नवप्रवेशी कार्यकताओं का स्वागत किया और विश्वास जताया कि इस पार्टी प्रवेश से वार्ड क्रमांक 15 में भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत होगी तथा संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी।

एक जनवरी से 31 जनवरी तक मध्यस्थता अभियान 2.0 का आयोजन

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ व जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर सुशील कुमार शशि के निदेर्शानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के तत्वावधान में 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान-2.0 चलाया जा रहा है। उक्त अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा। इस मध्यस्थता अभियान में वैवाहिक विवाद के मामलें, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चैक बाउन्स के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, सम्पत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, अन्य उपयुक्त दीवानी मामले आपसी सुलह-समझौतें के आधार पर निस्तारित किये जायेगें। अतः वादकारी गण एवं अधिवक्ता गण अपने-अपने वादों से सम्बन्धित न्यायालयों में सम्पर्क स्थापित कर वादों को मध्यस्थता हेतु संदर्भित करायें एवं अधिकतम वादों का निस्तारण कराकर उक्त अभियान का लाभ उठायें।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड Q3 FY26 बिक्री

मुंबईः 2 जनवरी 2026ः टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड द्वारा Q3 FY26 में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 171,013 यूनिट रही, जबकि Q3 FY26 में यह 139,829 यूनिट थी।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ, शैलेश चन्द्रा ने कहा, CY25 में पीवी इंडस्ट्री ने लगातार प्रगति देखी, जो एसयूवीएस के लिए बढ़ती पसंद, उत्सर्जन-अनुकूल पावरट्रेन को तेजी से अपनाने से प्रेरित थी। टाटा मोटर्स के लिए, यह लगातार पाँचवाँ साल था जब रिकॉर्ड तोड़ सालाना बिक्री हुई, जिसमें 587,218 यूनिट बेची गईं, जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में 81,125 यूनिट्स की अब तक की सबसे ज्यादा ईवी बिक्री भी शामिल है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, Q3 FY26 के आखिर में जीएसटी 2.0 के रोलआउट से मिली गति ने Q3 में और तेजी पकड़ी, जिसके परिणामस्वरूप कई नए रिकॉर्ड बने। हमने 171,103 यूनिट्स की अब तक की सबसे ज्यादा तिमाही थोक बिक्री हासिल की, जबकि रिटेल बिक्री/रजिस्ट्रेशन पहली बार 200,000 यूनिट्स के अहम पड़ाव को पार कर गया। नेक्सन ने अक्टूबर और नवंबर में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार/एसयूवी के रूप में नेतृत्व किया और Q3 FY26 के लिए इस नेतृत्व को बनाए रखने की राह पर है, जिसकी बिक्री प्त64,000 यूनिट्स रही। पंच ने अपने सेगमेंट में दबदबा बनाया और टियागो ने मजबूत ग्रोथ दी, जिससे हैचबैक पसंदीदा कारों में इसकी पसंद और मजबूत हुई। दिसंबर एक और शानदार महीना था क्योंकि हमने साल-दर-साल 22% की ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ की राह जारी रखी। साथ ही, हमारी रिटेल बिक्री थोक बिक्री से काफी ज्यादा रही, जिससे डीलर इन्वेंट्री घटकर प्त18 दिन हो गई, और मांग-आधारित ग्रोथ और समझदारी भरे चैनल हेल्थ मैनेजमेंट पर हमारे रणनीतिक फोकस को रेखांकित किया।

चोरी के अरोप में तमंचा सहित दो गिरफ्तार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। पुलिस ने चोरी की घटनाओं में शामिल दो आरोपीगण को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों से जंघई और मछलीशहर थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की दो बडी वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार मीरगंज थाना पुलिस ने थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। पुलिस टीम ने सेमरी करौर मार्ग पर महुआ के पेड के पास से संजय सिंह पुत्र फुल सिंह और विनोद कुमार पुत्र प्रीतम सिंह को हिरासत में लिया। दोनों कन्नौज जिले के रामनगर, थाना ठठिया के निवासी हैं। तलाशी के दौरान, आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा और 0.315 बोर का एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। उनकी जामा तलाशी में प्रत्येक से 2000-2000 रुपये भी मिले।प ूछताछ में आरोपियों ने 29/30 दिसंबर 2025 की रात जंघई रेलवे क्रॉसिंग, बभनियांव के पास एक मिठाई की दुकान के पीछे स्थित मकान का ताला काटकर चोरी के प्रयास की घटना स्वीकार की। इस संबंध में मीरगंज थाने में धारा 331 (4)305/62 बीएनएस के तहत मकदमा दर्ज है। उन्होंने 17 सितंबर 2025 को मछलीशहर थाना क्षेत्र में हुई एक अन्य चोरी की घटना में भी अपनी संलिप्तता कबूल की। इस वारदात में आरोपियों ने एक दुकान का ताला काटकर केमिकल डालकर घर में प्रवेश किया और अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर चुरा लिए थे। मछलीशहर थाने में इस मामले में धारा 305 बीएनएस दर्ज है। अवैध असलहे की बरामदगी के आधार पर मीरगंज थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया है।

पशु जागरुकता शिविर, पशुपालकों को मिला इलाज व प्रशिक्षण

सिवान (उत्तरशक्ति)। महाराजगंज बिहार के सिवान जिला अंतर्गत महाराजगंज प्रखंड के पोखरा पंचायत अंतर्गत पोखरा पंचायत सरकार भवन पर जीविका एवं पशु निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में पशु जागरूकता शिविर लगा। शिविर का शुभारंभ पंचायत में किया गया । भारत नारी शक्ति स्वावलंबी सहकारी समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर प्रखंड परियोजना प्रबंधक ने बताया कि शिविर का उद्देश्य केवल पशुओं का इलाज करना ही नहीं, बल्कि पशुपालकों को पशु रोगों की पहचान, बचाव एवं बेहतर देखभाल से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन देना है, ताकि पशुपालन को लाभकारी बनाया जा सके। वहीं कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी व पशुपालक ऐशो कुमार सिंह ने कहा कि पोखरा पंचायत में इस तरह का शिविर जीविका से जुड़े पशुपालकों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जिससे ग्रामीण स्तर पर पशुपालन को नई दिशा मिलेगी। पशु चिकित्सक अनिल कुमार मिश्रा ने ठंड के मौसम में पशुओं की विशेष देखभाल पर जोर देते हुए बताया कि इस मौसम में पशुओं को ठंड से बचाना, बुखार की पहचान कर समय पर इलाज कराना बेहद आवश्यक है।

क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का फॉलोअप, उपचार ले चुके रोगी स्वस्थ नजर आए

झुंझुनूं। राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं आयुर्वेद विभाग झुंझुनूं के संयुक्त तत्वावधान में एनआरडीडी अस्पताल परिसर, मलसीसर रोड पर आयोजित दस दिवसीय अंतरंग क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का शुक्रवार को फॉलोअप शिविर आयोजित किया गया। मुख्य शल्य चिकित्सक डॉ. सुनील कानोडिया द्वारा शिविर में उपचारित सभी रोगियों की पुनः जांच की गई, जिसमें सभी रोगी स्वस्थ, संतुष्ट एवं सकुशल पाए गए। शिविर प्रभारी एवं वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी डॉ. महेश माटोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 से 24 दिसंबर 2025 तक चले शिविर में कुल 103 रोगियों का सफल क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार किया गया था। फॉलोअप शिविर में डॉ. सुनील कुमार, डॉ. नवीन कुमार,डॉ. विकास कुमार, वरिष्ठ नर्स सुनिला व रीटा,कंपाउंडर सुनील कुमार,देवकरण और कुलदीप ने सराहनीय सेवाएं दीं। यह शिविर आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता एवं प्रभावशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण रहा।

महायुती के उम्मीदवार के समर्थन में भवानजी ने वापस लिया अपना नामांकन पत्र

प्रेम चंद मिश्रा

मुंबई (उत्तरशक्ति)। वरिष्ठ भाजपा नेता और मुंबई के पूर्व उप महापौर बाबूभाई भवानजी ने महायुती के उम्मीदवार के समर्थन में अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। भवानजी ने गुजराती, जैन, मारवाड़ी और सर्व समाज के और व्यापारी लोगों का आवाहन किया है कि वह महायुती के उम्मीदवार को विजयी बनाएं। भवानजी की मुलाकात उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से हुई जिसमें श्री भवानजी ने अपना नामांकन पत्र वापस लेने का एलान किया।

बता दें कि मुंबई के पूर्व उप महापौर और हिंदुवादी वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूभाई भवानजी ने अपने समर्थकों के साथ 29 दिसंबर को वार्ड नंबर 192 से अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। भवानजी के समर्थकों का कहना था कि मुंबई के कबूतर खाना बंद करने के विरोध में भवानजी को मैदान में उतारा गया है। इन लोगों का कहना था कि कबूतर खाना बंद करने से इस पक्षी प्रेमी,अहिंसा प्रेमी पहले से ही सरकार से नाराज हैं। भवानजी का कहना था कि वार्ड नंबर 192 से उनका रिश्ता 40 साल पुराना है। व्यवसाय और समाज कार्य इसी वार्ड में चलता है। मेरा घर परिवार यही रहता है। बता दें कि बाबुभाई भवानजी दादर विट्ठलवादी गणेश उत्सव मंडल, जैन हॉस्पिटल और वर्धमान जैन श्रावक संघ तथा दादर वेस्ट के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

बाबुभाई भवानजी कच्छी गुजराती , राजस्थानी,मराठी व्यवसायी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले समाजसेवी हैं। इस वार्ड में कुल 50713 मतदाता हैं। जिसमें 54 प्रतिशत मराठी, गुजराती, जैन, मारवाड़ी 15 प्रतिशत, उत्तर भारतीय दस प्रतिशत, दक्षिण भारतीय तीन प्रतिशत, क्रिश्चियन दो प्रतिशत, पंजाबी दो प्रतिशत, मुस्लिम दो प्रतिशत तथा अन्य बारह प्रतिशत हैं।

इस वार्ड में महायुति, कांग्रेस और शिवसेना उबाठा तीनों उम्मीदवार मराठी हैं जिससे उनके बीच मराठी मतों का विभाजन तय है जिसके चलते भवानजी की स्थिति काफी मजबूत थी। इस वार्ड में गुजराती, जैन, कटर हिंदूः सनातनी,कच्छी और मारवाड़ी समाज का वोट निर्णायक होने वाला है। यहां भवानजी की मौजूदगी से सभी मराठी उम्मीदवारों का खेल खराब हो सकता था। मुंबई में कबूतरों को दाना डालने पर पाबंदी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा था। मुंबई के कबूतरखाना पर तिरपाल डालने को लेकर पक्षी प्रेमी सनातनी और जैन समुदाय नाराज थे। उन्होंने ने कहा था कि वह धर्म के खिलाफ किसी की नहीं सुनेंगे। मुंबई में कबूतरों को दाना डालने पर जब से रोक लगाई है तब से बीएमसी एक्शन में है। बीएमसी ने कबूतरों को दाना डालने पर अब तक अनेक लोगों पर जुमार्ना लगाकर लाखों रुपये वसूले हैं। पक्षी प्रेमी, हिंदू, जैन ,सनातनी समाज की इस आक्रामकता के कारण इस वार्ड का चुनाव दिलचस्प हो गया था और बाबूभाई भवानजी इसी समाज की प्रेरणा से चुनाव में ताल ठोंक रहे थे।

इसी बीच शिंदे शिवसेना के नेता पूर्व सांसद राहुल शेवारेजी ने समाज के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे के निवास पर बैठक करवाई। भवानजी ने समाज की ओर से कहा कि जब तक पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है, तबतक कुछ टाइम के लिए कबुतर खाना खुला करे। जहां देवालय है वहां विद्यालय की स्थापना की जाए। गुरुकुल स्कूलो का निर्माण किया जाए, संस्कृत भाषा का संवर्धन किया जाए, जैन साधु संत जिन महामार्ग पर विहार करते है उन महामार्गों पर पदपथ रस्ते का निर्माण किया जाए,उस मार्ग परछावनी, पानी,शौचालय की व्यवस्था की जाए। मुंबई के फेरीवालो को न्याय दिलाया जाए और उनके ऊपर चल रही कार्यवाई स्थगित की जाए। एकनाथ शिंदे ने सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया।